THE DEPUTY CHAIRMAN: We shall now take up clause-by-clause consideration of the Bill.

*Clauses 2, and 3, and Schedule were added to the Bill.*

*Clause 1, the Enacting Formula and the Title were added to the Bill.*

SHRI M. V. CHANDRASHEKHAR MURTHY: Madam, I move:

That the Bill be returned.

*The question was put and the motion was adopted.*

---

THE DEPUTY CHAIRMAN: Thank you very much. Now, we have general discussion on the Budget. If the House agrees we can adjourn the House for one hour. It is two o' clock. Before I adjourn the House for lunch, I have to make an announcement. There is one statement by Capt. Satish Sharma, Minister of State of the Ministry of Petroleum and Natural Gas. He wants to make a statement regarding kerosene. Mr. Mathur has raised this matter in the House. He will make it at 5.30 p.m. There is also a request from Mr. Kalpanath Rai, Minister of State of the Ministry of Food, Government of India. He says in his letter, "I would like to make a statement on the import of sugar in the Rajya Sabha".

SHRI SATYA PRAKASH MALAVIYA (Uttar Pradesh): Import of sugar in Rajya Sabha!

THE DEPUTY CHAIRMAN: I am reading out his letter. It says:

> "I would like to make a statement on the import of sugar in the Rajya Sabha after the Question Hour is over. Kindly permit me to do the same at 5.00 p.m.:

There is a contradiction in his letter itself. He says "after the Question Hour" and that is at 5.00 p.m. We can call him at 5.00 p.m. and the other Minister at 5.30 p.m. Now, the House is adjourned for one hour for lunch. We will meet at 3.00 p.m.

The House then adjourned for lunch at fifty-nine minutes past one of the clock.

---

The House reassembled after lunch at three minutes past three of the clock, The Vice-Chairman (Shri Shankar Dayal Singh) in the Chair.

THE BUDGET (GENERAL), 1994-95.

डा० मुरली मनोहर जोशी: (उत्तर प्रदेश) : उपसभाध्यक्ष महोदय, वर्ष 1994-95 के बजट की जो कुछ समीक्षाएं हुई हैं जो कुछ इस बजट के प्रावधान है, उनको देखकर मुझे ऐसा लगता है कि अगले वर्ष इस देश के लिए भयानक आर्थिक तबाही के रूप में आएंगे । किसी भी बजट की कोई एक दिशा होती है । उसका एक दर्शन होता है । आम आदमी के लिए गरीब आदमी के लिए, देश की सामान्य जनता के लिए कुछ देन होती है । जब मैं इस बजट को देखता हूं तो मेरे सामने सवाल उठते हैं कि गरीब आदमी के लिए इस बजट ने क्या किया है, कुछ किया भी है या नहीं किया है । आदिवासियों, दलितों और हरिजनों के लिए इस बजट ने क्या दिया है । क्योंकि यह बजट अपने को राष्ट्रीय बजट कहता है । वह भारत का नेशनल बजट है । इस राष्ट्र में 50-60 प्रतिशत लोग निर्धन हैं, गरीब हैं, 70 प्रतिशत लोग देहातों में रहते हैं, झुग्गी-झोंपड़ियों में रहते हैं । इसलिए कोई भी बजट अगर राष्ट्रीय है और वह अपने आप को राष्ट्रीय कहता है तो यह जरूरी है कि इस बजट में 60 प्रतिशत-70 प्रतिशत जनता के लिए, आम आदमी के लिए व्यवस्थाए होनी चाहियें ।

इसने मलिन बस्तियों में, झुग्गी-झोंपडियों में रहने वालों के लिए क्या किया है, औद्योगिक विकास को बढाने के लिए क्या किया है, कृषि उत्पादन को बढाने के लिए क्या किया है, बेरोजगारी को दूर करने के लिए क्या किया है,आम आदमी की क्रय-शक्ति, आमदनी बढ़ाने

के लिए क्या किया है और सब से जरूरी बात यह है कि इस बजट में कितने साधन इकट्ठे हुए, फंड्स कहां कहां से आये और उनका उपयोग कैसे हुआ ? फंड्स, रिसीवड फंड फन्ड्स डिप्लोयड इसके बारे में अगर बजट साफ बात नहीं कहता तो उस बजट की समीक्षा करते समय यह ध्यान में रखना पडता है कि शायद बजट जितना कुछ बताना चाहता है, उससे कहीं कुछ ज्यादा छिपाना चाहता है। हमारे वित्त मंत्री जी ने इस बार अपना बजट बहुत शेर-ओ-शायरी के साथ शुरू किया। मैं नहीं समझता कि उनके बजट को देख कर इस शेर से ज्यादा जो मेरे पढ़ने में आया है और कोई उपयुक्त शेर होगा

"तुम्हें मालूम है कि खुशहालियों
की ख्वाहिश में,
ए-शहर ने कितने फकीर
मार दिए हैं।"

देश के सामने एक नक्शा रखा गया तरक्की का, विकास का, सब्ज बाग दिखाए गए, यूटोपिया पेश किया गया, लेकिन नतीजा यही है कि अमीर-ए-शहर ने बहुत सारे फकीरों को मार दिया, सिर्फ इसलिए कि लोगों की यह बताया जाय कि हम खुशहाल होते जा रहे हैं। अगर हम इस बजट के जो हमारे वित्त मंत्री जी ने उद्देश्य रखे थे उन पर गौर करें तो उन्होंने सब से पहले जो यह कहा था कि यह राजकीय घाटे को घटायेंगे 1992 और 1993 में, 1993 और 1994 में बराबर वह यह कहते रहे कि फिक्सल डिफिसिट, राजकोषीय घाटे को हम घटायेंगे। फिर उन्होंने यह कहा कि यह राजस्व घाटे को, रेवेन्यू डैफिसिट को भी घटायेंगे और फिर उन्होंने यह भी कहा कि वह देश का विदेशी और आंतरिक ऋण भी घटायेंगे और फिर उन्होंने यह भी कहा हैं जो कुछ सुधार किए जा रहे हैं उसमें जो एडजस्टमेंट्स होंगे, संशोधन होंगे उसका बोझ गरीब आदमी पर न पडे वह इसका भी इन्तजाम करेंगे।

वित्त मंत्री के स्पीच के पार्ट "ए" में पैरा 8, पेज 3-4 में इन्हीं उद्देश्यों का उन्होंने उल्लेख किया है। मुझे कहना है कि इसमें से एक भी उद्देश्य वित्त मंत्री पूरा करने में 1993-94 में असफल रहे और पिछले तमाम बजटों के निष्पादन में परफार्मेंस आफ बजट को देख कर मैं यह कह सकता हूं 1994 और 95 की परफोर्मेंस भी, इस बजट का निष्पादन भी उतना ही निराशावादी होगा, निराशाजनक होगा उतना ही गरीब आदमी के लिए नुकसान देह होगा जितने कि पिछले बजट हुए हैं।

अब आप जरा राजस्व घाटे की तरफ देखें, 1993-94 में 84,209 करोड की रेवेन्यू रिसीट्स की बात कही गई थी बजट का अनुमान बजट एस्टीमेट 84,209 करोड रुपए का था, लेकिन संशोधित अनुमान 76,166 करोड रुपए का, 8,000 करोड़ का घाटा राजस्व प्राप्तियों में हुआ। इसी तरह से कैपिटल रिसीट्स को अगर आप देखें पंजीगत प्राप्तियां उसमें 58,646 करोड पिछले वर्ष का संशोधित अनुमान था इस साल 59,615 करोड रखा गया। एक हजार की मिनिमल मार्जनली वृद्धि इसके अंदर करने की बात कही गई है। लेकिन जरा आप उधारों की तरफ ध्यान करें।

SHRI JAGESH DAESAI (Maharashtra): It is the Revised Estimates.

DR. MURLI MANOHAR JOSHI: Yes; earlier, it was Rs. 42,000 crores. Rs. 42,000 crores was the Budget Estimates. I am talking about the Revised Estimates. That is the actual performance. You have to judge the performance only from this.

**उपसभाध्यक्ष (श्री शंकर दयाल सिंह)** : जगेश जी, इनके बाद आप भी बोलने जा रहे हैं इसलिए बीच में न टोकें तो ठीक है।

**डा. मुरली मनोहर जोशी** : अगर आप उधारों की तरफ ध्यान देंगे तो आप देखेंगे कि 1990-91 में जो बोरोइंग्ज 32,550 करोड़ थी वह 1993-94 में 49,491 करोड़ हो गई और इस बार 48,915 करोड़ का हिसाब लगाया गया है।

लेकिन हम देखते है कि 1993-94 में बोरोइंग्स के लिए, उधारों के लिए 32,645 करोड का अनुमान किया गया था, लेकिन यह बढ़कर 19,491 करोड हो गया। मैं नहीं समझता कि यह 48,915 करोड़ से कहां तक बढ़कर जाएगा, 60 हजार करोड़ पर रुकेगा या 65 हजार करोड पर रुकेगा, यह कहना बहुत मश्किल है ? इसी तरह से आप ब्याज की ओर ध्यान दें। इसमें 37,500 करोड रुपए का ब्याज पिछली बार रिवाइड एस्टीमेंट में लिखा और इस बार यह अनुमान किया जा रहा है कि 46,000 करोड़ तक यह जाएगा। इसी तरह रेवेन्यू डेफसिट देखें तो यह भी निरंतर बढता जा रहा है। वर्ष 1990-91 में यह 17,585 करोड़ था, 1992-93 में बढकर 18,574 करोड हो गया वर्ष 1993-94 में बजट अनुमान था 17,630 करोड था और यह बढकर 34,048 करोड का है। इस साल बजट अनुमान है 32,727 करोड का और मैं नहीं समझता कि यह कहां जाकर रुकेगा 60 हजार पर रुकेगा या 70 हजार पर रुकेगा। अगर पिछले हिसाब से देखा जाय तो 64 कहजार करोड तक जाना चाहिए क्योंकि परफॉर्मेन्ट दुगने घोटे का है, जितना अनुमान किया था उससे दोगुना आपने उधार किया है, रेवेन्यू डफेसिट किया है इसी तरह से फिक्सड डैफसिट, राजकोषीय घाटा 30,959 करोड़ रूपए का अनुमानित था, लेकिन वह बढ़कर 58,551 करोड़ हो गया। इस साल आप 54,915 करोड़ का अनुमान कर रहे हैं, लेकिन यह भी पता नहीं कि कहां तक बढकर जाएगा। प्रायमरी डैफेसिट की भी हालत ऐसी ही है। यह 1991-92 में 7,719 करोड हुआ करता था और आज 1993-94 में बढकर 21,051 करोड है। आपने बजट अनुमान में --1041 करोड का प्रबंध किया था, आप चाहते थे कि यह घोटा घट जाएगा, लाभ में आप रहेंगे और कोई प्राइमरी डैफेसिट नहीं होगा, लेकिन प्रायमरी डैफेसिट मायनस 1041 करोड के स्थान पर 21,051 करोड है। इस साल आपने 8915 करोड का इतजाम किया है, पता नहीं ये आप कहां तक ले जायेंगे।

SHRI JAGESH DESAI: On a point of order. (*Interruptions*) I am talking of the principle. This is a wrong picture....

**उपसभाध्यक्ष (श्री शंकर दयाल सिंह)** जगेश जी ऐसा है कि इनके बाद आप ही बोलने जा रहे हैं।

I will request you to hear him first because you are going to be the next speaker.

**डा. मुरली मनोहर जोशी** : ब इस बजट का जो परफार्मेंस रहा है, पिछला बजट निष्पादन रहा है, उसके आधार पर यदि आप 1994-95 के बजट को आप देखेंगे तो एसा लगता है कि भारी घाटे, भारी उधार, भारी ब्याज और भारी नान-प्लान एक्सपेंडीचर इसमें है क्योंकि नान-प्लान एक्सपेंडीचर भी निरंतर बढता जा रहा है। इन्होंने 90,072 करोड रुपए का अनुमान लगाया था, यह बढकर 97,846 करोड हो गया और 1994-95 में यह बढ कर 1,06,117 करोड हो जाएगा। इसलिए 1993-94 के बजटीय एक्सपेंडीचर से जो बातें उभरकर आई हैं, वह बडी भयानक है। पहली बात तो यह है कि पिछले कई सालों की आर्थिक व्यवस्था का नतीजा यह हुआ है कि हमारे देश का सकल राष्ट्रीय उत्पाद या ग्रास नेशनल प्राडक्ट पर कैपिटा, प्रति व्यक्ति घट गया है। यह 310 डालर 1992 में हो गया जो कि 1991 में 330 डालर था। यह वर्ल्ड बैंक एटलस की रिपोर्ट है और आज भारत लो-इनकम कंट्रीज या न्यूनतम आय वाले देशों में 57वां स्थान रखता है और हमारी पर-कैपिटा इनकम 350 डालर से कम है। इसके साथ ही हमारी क्रेडिट रेटिंग भी बहुत लडखडायी हुई है। हमारी हाई डेट टू एक्सपोर्ट रेशियो काफी ऊंची है। यह 2.5 है। और संयुक्त राष्ट्र मानव विकास के सूचकांकों से, हुमन डवलपमेंट इंडिसेज के अनुसार

मानव के विकास में, मानव की क्वालिटी के विकास में, जीवन स्तर को ऊंचा करने की दृष्टि से आज भारत का स्थान 134वां है जहां चीन का 101वां, इंडोनेशिया का 108वां और फिलीपींस का 92वां है ।

तो अगर आप दुनिया से अपने तमाम पिछले सालों की आर्थिक प्रगति की तुलना करें तो आप कहां हैं, किस जगह हैं, पता चलेगा ? यह उसके सूचकांक हैं । मानव के जीवन की उन्नयन करने में भी आप असफल रहे हैं, ह्यूमन रिसोर्सेज को डवलप आप नहीं कर रहे हैं । उनके जीवन-स्तर को ऊंचा नहीं उठा सके हैं । इसलिए मैं आपका ध्यान विश्व बाल कोष यूनिसेफ के द्वारा फरवरी 1994 में प्रकाशित रिपोर्ट की ओर आकृष्ट करना चाहूंगा । इसके अनुसार मुझे लगता है कि सरकार का हमारी अर्थव्यवस्था पर कोई नियंत्रण नहीं रह गया है, आऊट आफ कंट्रोल हो गया है, उनके हाथ से बाहर जा रहा है । इस रिपोर्ट में सुधार के बारे में 1989 में जो दुनिया भर में आर्थिक सुधार किए गए, उसके बाद से बहुत से यूरोपीय देशों की क्या हालत हुई, उसका जिक्र है । उसकी गंभीर स्थिति का बहुत ही विस्तार से वर्णन किया गया है और यह कहा गया है कि सुधारों का कार्यान्वित करते समय मनुष्य जीवन की सामाजिक और मानवीय पक्ष की पूर्णतया उपेक्षा की गई है । उसी का नतीजा यह है कि भारत का स्थान आज 134वां है । परिणामस्वरूप इन देशों में, यूरोपीय देशों में उन सुधारों की आप यहां नकल करना चाहते हैं, उन सुधारों को आप यूरोपीय देशों के अनुसार यहां लाना चाहते हैं, जिसका नतीजा यह हुआ है कि उन देशों में जन्म दर घट गई, मृत्यु दर बढ गई, स्कूली छात्रों की संख्या कम हुई और कुल मिलाकर गरीबी और बेरोजगारी बढी, कई परिवारों के पास मृतक को दफनाने के लिए धन नहीं होता और ताबूत की जगत गत्ते के डिब्बे मनुष्य को दफनाने के लिए उपयोग किए जा रहे हैं । यही करीब-करीब आपने हिन्दुस्तान की हालत की है । ठीक इसी तरह से आपकी जो आर्थिक नीतियां रहीं, जो स्लिपेज रहीं आपकी फिजीकल परफोरमेंन्स में, उसका खुलासा आपने स्वयं अपनी आर्थिक समीक्षा में किया है ।

मान्यवर, मैं इस आर्थिक समीक्षा के पृष्ठ 6 के पैरा 8, 9, 10—राजकोषीय निष्पादन में विफलता के परिणामों की तरफ आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहूंगा पैरा 8 में कहा गया है ——

"समग्र राजकोषीय कार्य निष्पादन में हुई असफलता से केंद्र बाजार स्रोतों (सरकारी प्रतिभूतियों और सरकारी हुंडियों की नीलामी के माध्यम से) और भारतीय रिजर्व बैंक, दोनों से बडी मात्रा में उधार लेने को बाध्य हो गया है । पहली किस्त के उधार ने गैर-सरकारी क्षेत्र से निवेश योग्य संसाधनों का पूर्वक्षय किया और (इस प्रकार निवेश मांग को रोकते हुए) ब्याज दरों में गिरावट को कम किया गया । यह संभव है——"

इस ओर जरा ध्यान दें——

"यह संभव है कि उच्च स्तरीय सरकार उधार के औद्योगिक निवेश में सुधार के मार्ग में एक बाधा हो, हालांकि जहां तक चालू उत्पादन का संबंध था, व्यापक राजकोषीय घाटा आवश्यक वित्तीय क्षेत्र संबंधी सुधारों के संकुचन प्रभावों के लिए लाभदायक विस्तृत संतुलन की व्यवस्था कर सकता है ।"

पैरा 9 में आप कहते हैं——

"निवल विदेशी परिसंपत्तियों में वृद्धि सहित भारतीय रिजर्व बैंक से लिए गए दूसरी किस्म के उधार ने अर्थव्यवस्था में प्रारंभिक धन की वृद्धि को तीव्र किया ।"

"धन आपूर्ति में द्वीयी वृद्धि (प्रारंभिक राशि से तुलना करने पर) मुख्यतः दो कारणों से हुई—जनता

द्वारा अपने पास रखी मुद्रा में असामान्य रूप से बहुत वृद्धि जिसने धन आपूर्ति पर प्रारक्षित धन विस्तृत प्रभावों को संयत कर दिया, और बैंक ऋणों पर अवरोधी के कारण कड़ विवेकपूर्ण मानदंडों और प्रतिभूति घोटालों के बाद की घटनाओं के बाद की घटनाओं से सजगता का वातावरण बना ।"

पैरा 10—

"धन आपूर्ति में वृद्धि से संबंद्ध अड़चनों के बावजूद नकदी का विस्तार अगस्त, 1993 से मुद्रास्फीती में हुई तेजी से समायोजन करने हेतु पर्याप्त था ।"...

लेकिन हुआ क्या ?

"थोक मूल्य सूचकांक में बिन्दु-दर-बिन्दु वृद्धि की दर मार्च तक 7 प्रतिशत तक गिर गई और मार्च से जुलाई तक औसत 7 प्रतिशत रहा । यह बढ़कर अगस्त में 8 प्रतिशत के उच्च स्तर तक चला गया ।..."

और, अब आप ही के तमाम आर्थिक समीक्षा वाले कहते हैं कि जो आपने एडमिनिस्टर्ड प्राइसेस बढाई, जो आपने पब्लिक डिस्ट्रिब्यूशन के लिए प्राइसेस बढ़ाई, जो आपने अनाजों की कीमतें बढ़ाई, उस सब के नतीजे यह होंगे कि दो परसेंट आपका इन्फलेशन और बढ़ेगा और मैं अगर गलत नहीं कहता तो मार्च होते होते आपकी इनफलेशन की दर 10 प्रतिशत होने वाली है और अगर यह 12 प्रतिशत तक पहुंच गई तो आप 1990-91 की तरफ वापस लौटने के लिए कदम उठा रहे हैं । तो यह आपकी कान्सिक्वेन्सेस है स्लिपेज के , आपकी ओवरऑल फिजिकल परफोरमेन्सेस के । पिछले तीन बजटों के निरंतर रखे जाने का यह नतीजा हुआ है ।

आपने 1993-94 में जो रेवेन्यू रिलाइजेशन हुए उसकी कमी के कारण बताएं हैं — औद्योगिक विकास की रफ्तार घटी, आयात में कमी हुई, बढ़ते हुए सरकारी खर्च के दबाव से राजकोषीय घाटा काबू से बाहर हो गया, शुद्ध बैंक उधार में भारी वृद्धि हो गई, सरकारी उधार जो व्यापारिक बैंकों और सहकारी बैंकों से प्रतिभूतियों, हुण्डियों की बिक्री के रूप में संग्रह हुआ उसकी दर 25 परसेंट हो गई, जो कि गत वर्ष 1992-93 से लगभग दुगुनी है । पैरा 28, 29, 30 ईकोनोमिक सर्वे । यह आपकी परफोरमेन्स है, फिजिकल परफोरमेन्सेस ।"..डेट सर्विसिंग, अब आप टोटल इन्टरेस्ट पेमेन्ट्स देखते जाइए । 1990-91 में आपका संशोधित अनुमान 21,850 करोड़ था और 1993-94 में यह संशोधित अनुमान 37,500 करोड़ हुआ और इस बार 46,000 करोड़ रुपए का आपने बजट में अनुमान किया है और अगर इसको आप देखें तो यह आपकी रिवेन्यू रिसीट्स जो हुई है इस बीच में 1993-94 में 76,166 करोड़ और अब आप बजट एस्टीमेट करते हैं 86,084 करोड़रु., जरा इसकी तुलना कीजिए । तो रिवेन्यू रिसीट्स और इन्टरेस्ट पेमेंट 1993-94 में आपका अनुमान था रेशो 45 परसेंट होगी, लेकिन हुई थी 49.2 परसेंट । उसके बाद आप खुद कहते हैं कि यह 53.4 परसेंट तक जायगी । इसलिए अगर आप यह देखें तो 46 हजार करोड़ रुपये का यह टोटल आप इन्टरेस्ट पेमेंट कर रहे हैं। यह राजकोषीय घाटे का 8.5 परसेंट है और रक्षा प्रावधान के दुगुने के बराबर है । जितना आप टोटल डिफेंस एक्सपेंडिचर कर रहे हैं, उससे दुगुना आप ब्याज की पेमेंट कर रहे हैं । तो इस तरह से आपकी जो हैट डेट सर्विसिंग है, उसकी हालत सुधर नहीं रही है, निरंतर बिगड़ रही है । कर्ज की रफ्तार भी, स्वयं आपकी सरकार ने जो कर्जे के आंकड़े प्रकाशित किए हैं, 1993 तक आपका कुल विदेशी ऋण 2,86,000 करोड़ रूपये था । 1996-97 में जब भुगतान बिल्कुल अपने शीर्ष पर होगा, तब इसकी हालत कितनी होगी, किस हद तक हम जायेंगे, यह कहना कठिन है, इसका अनुमान लगाना मुश्किल नहीं है । आप इस देश को बिल्कुल फटेहाली की तरफ ले जा रहे हैं, ऋण जाल में ग्रस्त करते जा रहे हैं ।

इसके साथ - साथ आपको मैं बताना चाहता हूं कि आपकी इन तमाम नीतियों का

नतीजा यह हुआ कि प्लान योजना के लिए जो व्यय किया जा रहा था, उसमें निरंतर ह्रास होता जा रहा है, बजटरी सपोर्ट आप निरंतर घटाते जा रहे हैं । 1987-88 में प्लान के लिए बजटरी सपोर्ट 60.6 परसेंट हुआ करती थी, आज 1993-94 में घटकर 36परसेंट रह गई और 1994-95 में 39 परसेंट आपने इसके लिए तर्क यह दिया है कि आप बहुत से सरकारी उपक्रमों के लिए बाहर से पैसा जुटाएं और उसके लिए आपने एक नीति बनाई है । आपके इक्नामिक सर्वे का पेज 29, पैरा 2.28 कहता है :-

"This is in keeping with the policy of the Government to bring about greater accountability and self-reliance in the working of public sector undertakings so that funds are raised from the market as far as possible."

आज बाजार से इन तमाम सरकारी उपक्रमों के लिए सैंट्रल प्लान में पैसा बाहर से लाया जा , इसका इंतजाम करना चाहते हैं मगर नतीजा क्या है, इसको अगर आप जरा गौर से देखेंगे तो मैं आपको सिर्फ पहले पब्लिक सैक्टर अंडर टेकिंग में पावर सैक्टर का एक उदाहरण देता हूं । 1989-90 में इसको बजटरी सपोर्ट थी 1200 करोड़ रुपए की, 1992-93 का रिवाइज्ड एस्टीमेट 292 करोड़ 1993-94 में आप प्रपोज करते थे 640 करोड़ रुपए, कितना हुआ मुझे मालूम नहीं, अब आप एक्सट्रा बजटरी सपोर्ट, जो इनको दिलाना चाहते थे कि ये बाजार से उठाएं एक्सट्रा बजटरी सपोर्ट के तौर पर 2,347 करोड़ लेकिन एकच्युअल हुआ 218 करोड़ । यह आपकी परफारमेंस है इन सैक्टर्स की । पावर सैक्टर, जो आपका सबसे महत्वपूर्ण सैक्टर है, जो आपके अंतरधारित्रों का, इन्फास्ट्रक्चर का एक बहुत महत्वपूर्ण आयाम है , जिस पर देश की औद्योगिक प्रगति निर्भर करती है, उसमें आपकी परफारमेंस यह है । उसके बाद आप खुद कहते हैं कि इसके कारण से बिजली के बहुत सारे प्रोजेक्ट्स के बिस्तार में बहुत बाधायें आई । और भी इसके अलावा आपकी परफारमेंस इन तमाम अंतर-धारियों के निर्माण के बारे में एक और उदाहरण देना चाहता हूं कि कितनी निराशा-जनक रही । मार्च 1993 में 26,842 करोड़ एक्सटर्नल असिस्टेंस के ऐसे जो डिस्कर्स नहीं किए जा सके और इसलिए उनका कोई उपयोग नहीं किया जा सका सका--26,842 करोड़, मामूली धनराशि नहीं है । यह आपने विदेशी से सहायता ली और उसके बाद उसका उपयोग नहीं किया । पावर सैक्टर के लि और महत्वपूर्ण सैक्टर्स के लि इसका उपयोग किया जा सकता था, देश में बड़े पैमाने पर अंतरधारित्रों का विकास किया जा सकता था, ग्रामीण विद्युतीकरण किया जा सकता था, स्टेट इलैक्ट्रिसिटी बोर्ड की हालत सुधारी जा सकती थी, लेकिन आपने इन 26,842 करोड़ का कोई उपयोग नहीं किया । अब जरा आप सैंट्रल प्लान आउटले की तरफ मैंने आपको बताया था कि इसमें आप यह देखें कि टोटल सैंट्रल प्लान की मात्रा तो बढ़ती जा रही है लेकिन उसमें बजटरी सपोर्ट घटता चला जा रहा है। और जो वृद्धि हो रही है, उसके नतीजे क्या निकल रहे हैं, उसके नतीजों के बारे में भी मैं आपसे चर्चा करूंगा कि किस तरह आप के इन तमाम उपायों के पश्चात भी देश के आर्थिक और औद्योगिक विकास में कोई प्रगति नहीं हुई । मुद्रा विस्तार का मैं पहले ही उल्लेख कर चुका हूं कि हमारी इकोनमी में इस समय काफी दबाव इस बात के पैदा हो रहे हैं । जो आप बहुत बड़ी मात्रा में 13 बिलियन डालयर विदेशी मुद्रा के भंडार की बात करते हैं, मेरा आपसे अनुरोध है कि जरा यह भी देख लें कि यह राशि खुद कितने बड़े इन्फशनरी दबाव को पैदा करेगी । इस का भी एक दबाव इस देश के अंदर पैदा हो रहा है । आप खुश हो रहे हैं कि आप के भंडार भरे हुए हैं लेकिन मुझे अफसोस है कि पिछले दिनों कैपिटल गुड्ज के क्षेत्र में इंपोर्ट बहुत घटा है और आपके पास भंडार बढ़ गए तो ज्यादा खुश होने की जरुरत नहीं है । कर्जे से लिया हुआ पैसा, इंपोर्ट के अभाव में पड़ा हुआ पैसा क्योंकि अगर आपने इंपोर्ट नहीं किया, कैपिटल गुड्ज का यहां पर उत्पादन नहीं किय

भारत का औद्योगिक निवेश जिसके लिए आप बहुत बड़ी मात्रा में विदेशी मुद्रा की जरुरत समझते हैं, उसका उपयोग नहीं हुआ तो यह हिंदुस्तान के उद्योगों की खस्ता हालत की तरफ दिग्दर्शन देता है।

इसलिए आपके सुधारों का क्या नतीजा हुआ इन उद्योगों के बारे में, उसका यह एक सूचक है। यह जाहिर करता है कि पिछले 3 सालों में आप हिंदुस्तान की औद्योगिक प्रगति के लिए कुछ नहीं कर पाए है। वह प्रगति निरंतर घटती रही है और पिछले साल, मुझे अगर आप इजाजत दें, उसकी परफॉरमेंस बहुत ही कमजोर रही है। आपके पास विदेशी मुद्रा का भंडार है, उसका आप उपयोग नहीं कर पा रहे हैं। आपके पास विदेशी सहायता का भंडार है पॉवर सैक्टर में, उसका आप उपयोग नहीं कर पा रहे हैं। हिंदुस्तान के बाजार से आपके उद्योग पैसा नहीं उठा पा रहे हैं और वह उद्योग जो महत्वपूर्ण है, जिसकी महत्ता यहां के उद्योग खुद समझते हैं, यहां की जरता खुद समझती है, उसमें भी आप पैसा नहीं उठा पा रहे हैं। तो इसका नतीजा यह है कि परफॉरमेंस ऑफ इकॉनमी, आपकी अर्थ-व्यवस्था का संचालन, उसका निष्पादन जिन हाथों में है, वह इनकम्पीटेंट हैं, वह दक्ष नहीं है।

मुझे बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि पिछले 3-4 सालों में लगातार भारत के औद्योगिक विकास में गिरावट आई है। भारत में रोजगार नहीं बढ़ा है, भारत में कृषि क्षेत्र के अंदर विकास नहीं हुआ है और भारत के लघु उद्योगों की हालत तो बहुत खस्ता हुई है। आपके इसी कार्यकाल में जो प्राईमरी आर्टिकल्स है, मूलभूत आवश्यकता की वस्तुएं हैं, उनकी कीमतों में भारी वृद्धि हुई है। हालत यह है कि सब्जियों की कीमत पिछले दिनों में जनवरी 15 तक 39.1 परसेंट हो गई है जिसमें अकेले आलू की कीमत 31 परसेंट से बढ़ी है और प्याज की कीमत 96.4 परसेंट से बढ़ी जो जनवरी 15 तक 134.7 परसेंट बढ़ी। चाय की कीमत 11.7 परसेंट बढ़ी और कॉफी 26.7 परसेंट और शायद अब 28 या 29 परसेंट तक बढ़ी गई है। इस तरह से नॉन-फूड आर्टिकल्स, जिसके अंदर चीनी और तिलहन और बाकी इस तरह की चीजें आती हैं, उसमें भी 17 से 18 परसेंट तक वृद्धि हुई और फ्यूअल में, पावर में, बिजली में, जो यह सब-ग्रुप हैं, इसमें 8.8 परसेंट कीमतों में वृद्धि हुई। तो इस तरह से आप कीमतों की वृद्धि को भी नहीं रोक पा रहे हैं। मुद्रा विस्तार को भी नहीं रोक पा रहे हैं, आप अपने औद्योगिक विकास की दर को नहीं बढ़ा पा रहे हैं

तो इसलिए मैं यह कहना चाहता हूं, मैं यह जानना चाहता हूं कि आपने जो वायदा किया था, जो आप बहुत दिनों तक हमारे देश के लोगों को समझाते रहे कि हम कृषि-उत्पादन बढ़ाएंगे, हम औद्योगिक उत्पादन बढ़ाएंगे और हम इस देश के अंदर रोजगार बढ़ाएंगे, उनमें से एक भी आपका जो वादा था, 1991-92 के बजट का, न 1992-93 के बजट का, न 1993-94 के बजट का पूरा हुआ। आप भी अध्यापक हैं, मैं भी अध्यापक हूं। अगर 3 साल तक लगातार लड़का एक ही क्लास में फेल हो जाए तो फिर उसको रेस्टीकेट करने के अलावा और कुछ बचता नहीं है। उसको इजाजत नहीं दी जा सकती कि वह इम्तहान के अंदर फिर से दोबारा बैठ सके।

SHRI VITHALRAO MADHAVRAO JADHAAV (Maharashtra): Is it a Budget of Professors?

DR. MURLI MANOHAR JOSHI: He claimed in his own Budget speech - while mentioning about education —that he was academician, I am... (*Interruptions*)...

SHRI VITHALRAO MADHAVRAO JADHAV: Experimental or theoretical?

DR. MURLI MANOHAR JOSHI: I do not know whether he is a theoretical economist. But I am an experimental physicist.

**उपसभाध्यक्ष (श्री शंकर दयाल सिंह)** : जोशी जी, रिटायर्ड प्रोफेसर को तो कोई खतरा नहीं है ?

**डा० मुरली मनोहर जोशी** : न रिटायर्ड को खतरा है और न ही कार्यरत प्रोफेसर को खतरा है । खतरा है उस वित्त मंत्री को जो 3 साल तक लगातार फेल होता रहा । अब आपने कहा है कि आपके खाद्य भंडार बहुत ज्यादा बढ़े हुए हैं । करीब 23 मिलियन टन के खाद्य भंडार आपके पास पड़े हुए हैं । कैसे बढ़ गए ? आपके निर्गम मूल्य जो हैं, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम से, सस्ते मूल्य की दुकानों से, वह आपने बढ़ा दिए । आज बाजार में और इस सार्वजनिक प्रणाली में मूल्यों का अंतर बहुत कम हो गया है। इसलिए आप का जो फूड कारपोरेशन है उससे उठान, सामान का निष्कासन कम हो गया है । अगर आप पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के दामों में और खुले बाजार के दामों में अंतर घटाते चले जाएंगे तो आपने गैट का पालन उस पर हस्ताक्षर करने से पहले शुरु कर दिया है, तो योजनाबद्ध तरीके से हिन्दुस्तान की सार्वजनिक वितरण प्रणाली को आप नष्ट कर देना चाहते हैं। अगर आप पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को नष्ट कर देंगे तो इससे देश को बहुत बड़ा नुकसान होगा । आदिवासी क्षेत्रों में, दलित क्षेत्रों में, झुग्गी-झोंपड़ी में रहने वाले लोग जो कि इससे मुख्य रूप से लाभान्वित हो रहे हैं उन के ऊपर आप ने कहर बरपा किया है । यह एक ऐसा माध्यम था कि जिसमें आप उनको सहायता पहुंचा रहे हैं, और अगर आपने इस सार्वजनिक वितरण प्रणाली को नष्ट कर दिया, इस में काम करने वाले लोगों को आप नष्ट कर देंगे तो उसका नतीजा देश की अर्थ-व्यवस्था के लिए बहुत खतरनाक होगा । इसलिए मैं चाहता हूं कि आप इस पर गौर करें कि आप जिस बात के लिए वाह-वाही लूटना चाहते , कल वह आपके लिए तबाही का कारण न बन जाए ।

अब थोड़ा मैं रोजगार की तरफ जाना चाहता हूं । इस देश में सबसे प्रमुख समस्याओं में से एक समस्या रोजगार की है। बेरोजगारी इस देश में भारी पैमाने पर बढ़ रही है । आपकी 8वीं पंचवर्षीय योजना में आप लिखते हैं कि वे लोग जो नए रोजगार की तलाश में आएंगे उनकी संख्या अप्रैल 1992 तक 23 मिलियन थी, 1992–93 के बीच में आपका प्रोजेक्शन 35 मिलियन का है, 1997 से 2002 तक 30 आप 36 लाख की बात कर रहे हैं। कुल नए ऐम्लायमेंट की आवश्यकता 1992–93 तक आपको 58 मिलियन है, 1992 से 2002 तक 94 मिलियन है, इस तरह से आपको 4 परसेंट ग्रोथ आफ ऐम्लायमेंट, रोजगार दर में वृद्धि करनी है अगर आप ने सब को जो 1997 तक का प्लान है उनको रोजगार दे देना है । और अगर आप आखीर तक यानि 2002 तक भी दे दें तो भी 3 परसेंट से ज्यादा रोजगार की दर में वृद्धि करनी होगी । लेकिन आपका प्लान कहता है और मेरा ख्याल है कि आपके आंकड़े यह बताते हैं कि यह 4 परसेंट रेट आफ ग्रोथ फिजिबल नहीं है । अब आप कहते हैं कि—

within the realm of feasibility, 2.6 to 2.8 per cent

ग्रोथ संभव है । इसका अर्थ यह है कि 1992 से 1997 तक के लोगों को आप रोजगार दे ही नहीं पाएंगे । आप 2002 तक भी सब किसी को रोजगार नहीं दे पाएंगे । इस पर आप अगर गौर करें तो आप का हर साल का रोजगार का बैकलॉग न रहे । नये लोगों को रोजगार मिले, इसके लिए 8 से 9 लाख लोगों के प्रतिवर्ष रोजगार देना होगा । इसलिए इस साल में जो बजट आप का है आपको 8 मिलियन लोगों को रोजगार देना है लेकिन आप ने 1991–92 में 3 मिलियन और 1992–93 में 6 मिलियन, कुल मिलाकर आप खुद कहते हैं कि 9 मिलियन लोगों को रोजगार मिला जब कि आप को कुल 18 मिलियन को रोजगार देना था । तो आपके उदारीकरण, सुधारीकरण और उधारीकरण के कारण जो भयावह लक्षण सामने दिखाई दे रहे हैं उनकी ओर आपका ध्यान नहीं गया है । क्या आपके रोजगार की बेहतर स्थिति रही ?

श्रीमन, प्राइवेट इंडस्ट्रियल सेक्टर और पब्लिक इंडस्ट्रियल सेक्टर, फिर लघु उद्योग,

कृषि, हैंडलूम, पावरलूम, ये तमाम सैक्टर हैं जिन का विश्लेषण कर लिया जाए । आपका इकानामिक सर्वे कहता है कि तमाम भारी इंवैस्टमेंट के बावजूद प्राइवेट इंडस्ट्रियलज सेक्टर में 1986 से 1991 तक 3 लाख से अधिक रोजगार पैदा नहीं हुए और पब्लिक सेक्टर के अंदर तो कोई भी ऐंप्लायमेंट वृद्धि नहीं हुई, इन पिछले 5 सालों में नहीं हुई ।

इसके अलावा आप जरा गौर करें कि आपका इंवैस्टमेंट क्या था । 31-3-91 से 31-3-93 तक गवर्नमेंट सेक्टर के पब्लिक ऐंटरप्राइजेज में 33075 करोड़ रुपए का इंवैस्टमेंट आपने दो सालों में किया और ऐंप्लायमेंट की हैल्थ क्या है, वह मैं आप को बताना चाहता हूं । 1991 में आपका ऐंप्लायमेंट था 21.19 लाख, 1991-92 में 21.79 लाख और 1992-93 में 21.37 लाख । वह घट गया कुल 1.80 और .93 परसेंट । 33 हजार करोड़ रुपये का इन्वेस्टमेंट और लाभ कितना है आपको ? आप इस एडीशनल इन्वैस्टमेंट के ऊपर नार्मल बैंक रेट को भी लें तो कितना लाभ होगा ? 16 परसेंट विदेशी कम्पनियों को एश्योर्ड गारण्टीड प्रोफिट पर चलाने की आप इजाजत देते हैं लेकिन अपने पब्लिक सेक्टर के इन्वेस्टमेंट के लिए आप क्या कर रहे हैं ? इनको प्रोफिटेबल क्यों नहीं बना रहे हैं । इस बड़े भारी इन्वैस्टमेंट के बाद आपके मुनाफे की जनरेशन की क्या हालत है ? आप पब्लिक सेक्टर के क्षेत्र को कब ठीक कर पायेंगे, कब आप इसको मुनाफे में परिवर्तित कर पायेंगे, प्रोफिटेबल बना पायेंगे ? आप कब कम्पीटेटीव बना पायेंगे, कब आप इसे प्रोडेक्टिव बना पायेंगे ? आप तमाम बाहरी कारपोरेट सेक्टर के लिए बातें करते हैं लेकिन जो खुद आपके अधिकार में हैं, जिनको सरकार चला रही है उसकी पिछले तीन सालों में क्या हालत रही है ? दूसरी तरफ आप देखें स्माल स्केल इंडस्ट्री में 13 मिलियन लोग काम करते हैं ? हैंडलूम में 14 मिलियन लोग काम करते हैं, खादी एंड विलिज में 5 मिलियन लोग काम करते हैं । ये 32 मिलियन लोग एक ही क्षेत्र में काम करते हैं । जरा इनकी इन्वेस्टमेंट को देखें । आपने क्या इन्वेस्टमेंट किया है इसमें ? स्माल स्केल में 1991 से 1993 तक 630 करोड़ और खादी में 134 करोड़ एम्पलायमेंट जनरेट यहां हो रहा है, इन्वेस्टमेंट आप इनके लिए यहां कितना थोड़ा कर रहे हैं जिस सेक्टर में आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं उससे गरीब आदमी को क्या फायदा पहुंचेगा ? उससे आदिवासी को क्या फायदा पहुंचेगा ? उससे ग्रामीण बेरोजगार को क्या फायदा पहुंचेगा ? उससे पढ़े-लिखे बेरोजगार को क्या फायदा पहुंचेगा ? एक लाख से अधिक डेढ़ लाख के करीब अगर डाक्टर्स, इंजीनियर्स, स्पेस साइंटिस्ट्स और पी0एच0 डीज इस देश में बेकार पड़े हुए हैं उनके लिए आप क्या कर रहे हैं ? उनके रोजगार उत्पादन के लिए आपने पिछले तीन सालों में क्या किया ? 94-95 के बजट में रोजगार उत्पादन के लिए आप कौन सी योजना चला रहे हैं ? अगर आप पुरानी जवाहर रोजगार योजना को लें, प्रधान मंत्री रोजगार योजना को लें, उनका अगर चिट्ठा खोलूं तो आपकी स्वयं की समीक्षाएं कहती हैं कि उनमें हर साल गिरावट आई है । हर साल आपकी रोजगार दिलाने की संख्या घटती चली जा रही है ।

हैंडलूम क्षेत्र की समस्याएं बहुत गम्भीर हैं जिनके निदान के लिए आपने कोई इंतजाम नहीं किया । देश को याद होगा, सदन को याद होगा कि पिछले दिनों कुछ समय पहले आन्ध्र प्रदेश में 70 परिवार बुनकरों के भूख से मर गये थे । आज भी इन तमाम हैंडलूम लोगों की हालत बहुत खराब है । उनके लिए जीवनयापन की कोई व्यवस्था नहीं है । आज हालात उसी तरफ फिर से बढ़ रहे हैं । न आप उनको धागा ठीक दाम पर दे पा रहे हैं, यार्न की कीमत तो बढ़ ही गई है आपकी नीतियों के मुताबिक, और न ही जो वे प्रोडयूज कर रहे हैं उनके लिए कोई मार्किट ढूंढ पा रहे हैं । हैंडलूम को आप कम्पीट करवाना चाहते हैं पावरलूम से और पावरलूम को कम्पीट करवाना चाहते हैं मिलों से । हमारी मिलों को कम्पीट करवाना चाहते हैं फारेन से । आप बड़ी मिलों का कम्पीटीशन कर रहे हैं वह तो शायद बर्दाश्त कर लेंगे लेकिन हैंडलूम बेचारों को आप कम्पीटीशन के लिए क्यों मजबूर कर

[डा मुरली मनोहर जोशी]

रहे हैं ? इसमें सुधारीकरण की आपकी क्या व्यवस्था है । किस ढंग से आप इन लाखों लोगों को जो रोजगार का बहुत बड़ा साधन हैं, ग्रामीण रोजगार का साधन हैं, जो लोगों को घर बैठे रोजगार देना चाहते हैं, मैं वित्त मंत्री जी से पूछना चाहता हूं आपने सारे बजट में उनके लिए क्या व्यवस्था की है ? यह सबसे अधिक रोजगार देने वाले, एम्पलायमेंट जनरेशन की केपेसिटी इसमें सबसे ज्यादा है और यही वह क्षेत्र है जो एक्सपोर्ट भी आपका सबसे ज्यादा करता है । आप इनकी तरफ क्या ध्यान दे रहे हैं ? इस बजट को देखने पर मुझे तो बिल्कुल निराशा लगी कि आप इन तमाम क्षेत्रों को, जो परम्परागत क्षेत्र हैं, जो सदियों से, हजारों सालों से हिन्दुस्तान के फारेन ट्रैड को बढ़ाते रहे हैं, इसमें हमारा नाम रहा है, कपड़े के व्यवसाय में तो उस सारे व्यवसाय को आपने चौपट कर दिया । यह आपकी नीतियों का नतीजा है । अब आप डंकल ड्राफ्ट पर, गैट सेकिण्ड पर हस्ताक्षर करने जा रहे हैं उसके बाद इनका क्या नतीजा होगा यह भगवान जानता है । मैं कांप उठता हूं जब मैं सोचता हूं आपकी इन तमाम नीतियों के परिणाम पर । देश के इस वर्ग पर जो बिल्कुल सर्वहारा है, जिसको आप गरीब कहते हैं, दरिद्र नारायण हैं, जो सबसे निचले तबके में खड़ा है उसके लिए आप सोमालिया जैसे हालात पैदा करने के अलावा और किधर ले जाना चाह रहे हैं ? 70 परिवार रिकार्ड में हैं जो भूख में मरे और उससे अधिक न मालूम और कितने भूखमरी के कगार पर खड़े हैं उनकी तरफ आपका कोई ध्यान नहीं है । दूसरी तरफ आप जिन यूरोपीय देशों की नकल करना चाह रहे हैं उनकी हालत क्या है ? बेरोजगारी की समस्या तो वे भी हल नहीं कर पाए। सुधारीकरण से मैंने आपको पहले ही बताया कि मानव के जीवन के स्तर को आप नहीं उठा पाये लेकिन आप सुधारीकरण वाले उन यूरोपीय देशों की तरफ गौर करें तो बरोजगारी की समस्या उनके सामने भी मुंह बाये खड़ी है । दो करोड़ के लगभग लोग आज यूरोप यूनियन के एक दर्जन देशों में बेरोजगार पड़े हुए हैं । इंगलैंड मंदी के दौर से गुजर रहा है । अमेरिका की बहुत सी कंपिनियों में छंटनी हुई है । वित्त मंत्री हमें उन देशों के साथ नत्थी रखना चाहते हैं, हमारे देश की अर्थ-व्यवस्था को उनके साथ जोड़ने के लिये उनकी बेरोजगारी को हमारे यहां ट्रांसफर करना चाहते हैं । हमारे हैंडलूम कपड़ा व्यापारी, सीमांत बेरोजगार किसान, भूमिहीन किसान उनकी और अधिक दरिद्रता की तरफ, अधिक भुखमरी की तरफ धकेलने के लिये हमारे बाजार को उनके लिये खोलना चाहते हैं। आपके बजट में जो व्यवस्थायें हैं वह हमें उस तरफ धकेल रही हैं । आप देखें कि लघु उद्योग के साथ आपने क्या किया । जो एक्साइज का प्रावधान है, उत्पाद शुल्क का प्रावधान है उसके कारण 22 लाख इकाइयों में से पांच लाख लघु इकाइयां बंद होने के कगार पर हैं । आपने श्रमिकों को हड़ताल पर जाने की बात तो सुनी होगी लेकिन इस बार उद्योग में हड़ताल हुई है । यह, मैं समझता हूं कि एक बहुत ही विशेष आपकी उपलब्धि रही है ।

अभी तक हम केवल श्रमिकों की हड़ताल सुनते थे लेकिन इस बार उद्योगों की हड़ताल सुन रहे हैं, स्माल स्केल इंडस्ट्री हड़ताल पर थी । अगर ये पांच लाख की पांच लाख यूनिट बंद हो गयी तो इससे 30 लाख के लगभग लोग बेरोजगार हो जायेंगे और नये बेरोजगारों की संख्या से यह नया एडीशन होगा, नया जोड़ होगा । इंजीनियरी, कपड़ा और रसायन क्षेत्र में कुल रुग्ण इकाइयों की संख्या 22 प्रतिशत है और इन इकाइयों पर बैंकों की बकाया राशि 38 प्रतिशत है । आपकी नीतियां ऐसी हैं जिनके कारण ये बेचारे कभी भी इस रुग्णता से उभर नहीं सकते । आप इनकी कोई मदद नहीं करना चाहते आप इनकी वर्किंग कैपिटल के लिये लोन नहीं देना चाहते हैं । इन उद्योगों की आर्थिक हालत अच्छी हो ताकि ठीक टाइम पर वह पैसा वापस हो, इसकी व्यवस्थ आप नहीं करना चाहते हैं । ये कम्पीटीटिव बन सकें इसके लिये आप इनको कोई राहत नहीं देना चाहते हैं । आपका तमाम अगला कोटा-परमिट आदि में ब्यूरोक्रेटसइ की तरफ बढ़ रहा है और इसके कारण इन

लोगों को रोज-रोज जो इंसपेक्टर वहां जाते रहते हैं उनसे निबटना पड़ता है । इसकी तरफ आपका ध्यान कम है । आपने 1994–95 के बजट में जो एक्साइज ड्यूटी लगायी है उसमें 106 करोड़ रुपये की जो अतिरिक्त आमदनी है उसमें करीब-करीब 100 करोड़ लघु उद्योग से आप वसूलने जा रहे हैं । इसका नतीजा यह है कि इलैक्ट्रोनिक्स का सामान, हल्की इंजीनियरी का सामान, टेली-कम्युनिकेशन, दूर-संचार और आटो कल-पुर्जों से संबंधित जितनी भी इकाइयां हैं वे पूरी तरह से लड़खड़ा गयी हैं । मैं कल मुंबई में था वहां मुझे कुछ लोग मिलने आये जो स्माल स्केल इंडस्ट्री के थे । वे रो रहे थे । वे कह रहे थे कि अगर आपको वित्त मंत्री कहीं मिले तो उनसे हमारी तरफ से हाथ जोड़कर प्रार्थना कीजिये कि वे इस तरफ ध्यान दें । जो शेरो-शायरी उन्होंने अपनी बजट स्पीच के दौरान की उसमें हमें लगा कि उनमें संवेदनशीलता है, काव्यात्मकता है, उन्होंने एक कवि का हृदय वहां जो दिखाया वही हृदय वे हमारी तरफ भी दिखायें और इस उद्योग ने जो इस देश की अर्थव्यवस्था के बहुत बड़े हिस्से को संभाला हुआ है, वे जरा इसकी मुफलसी की तरफ ध्यान दें । आप आये नहीं थे । मैंने भी काव्यात्मक रूप में बोलते हुए यह कहा था कि "कितने सारे फकीर शहरे अमीर ने मार दिये, इस देश की खुशहाली के खातिर" । तो आपने खुशहाली को लाने के लिये, शहरे अमीर ने फकीरों की जान पर तलवार चला दी, उन फकीरों पर जिन्होंने हिन्दुस्तान को हिन्दुस्तान बनाये रखा है । जिन्होंने इस देश की शान को बनाये रखा है । आप ऐसे इस फकीर की तरफ ध्यान दीजिये जिसने हिन्दुस्तान की आजादी की लड़ाई में महात्मा गांधी के रूप में काम किया और जिसने देश को दरिद्र नारायण की उपासना का संदेश दिया था, स्वामी विवेकानन्द से दीन दयाल उपाध्याय तक ने जिनकी उपासना की बात कही, उन लोगों ने आपसे दरख्वास्त की कि आप देश के इन लोगों की ओर जिनकी जनसंख्या देश की कुल जनसंख्या का 70 प्रतिशत है, उनकी तरफ ध्यान दें और उनके लिये आर्थिक सुधार लाने के लिये, उनका जीवन उठाने के लिये कुछ करें, खाली शेरो-शायरी से इस देश का भला होने वाला नहीं है ।

आपने आयुर्वेदिक दवाओं पर भी 10 प्रतिशत उत्पाद शुल्क लगा दिया है । एक तरफ तो विदेशी दवाओं के दाम बढ़ने की बड़ी संभावना है और दूसरी तरफ आप आयुर्वेदिक दवाओं के दाम बढ़ा रहे हैं । मुझे आपसे इस बात की शिकायत है कि जब आपने ड्यूटी लगायी तो आपने कहा कि आल्ट्रनेटिव मेडीसिन । इस देश में क्या आयुर्वेदिक आल्ट्रनेटिव मैडिसिन है ? दुनियां के लोगों को जब दवाइयों की तमीज नहीं थी, उस समय इस देश में आयुर्वेदिक का विकास हुआ था और धनवन्तरी, चरक और सुश्रुत ने ईसा से हजारों साल पहले दुनियां को दवाओं का सिस्टम दिया था । दुनियां में आयुर्वेद ने ही सबसे पहले यह बताया कि किसी तरह से बीमारी लोगों के अंदर न फैले । बीमारी फैल जाना यह इलाज नहीं है, आयुर्वेद में यह व्यवस्था है कि बीमारी ही न फैले और इसके लिये उसमें इंतजाम है । "मा कश्चित् दुःख भागभवेत्"

यह आयुर्वेद का सिद्धांत है । यह आत्मा और शरीर दोनों को बलवान बनाने का सिद्धांत है । आप इसको आल्ट्रनेटिव सिस्टम कहते हैं । आल्ट्रनेटिव सिस्टम तो ग्रीक सिस्टम हो सकता है, यूनानी सिस्टम हो सकता है, ऐलोपैथी सिस्टम हो सकता है लेकिन आयुर्वेद सिस्टम नहीं । यह दुनियां में सबसे पहले आया और यह दुनियां की सबसे पुरानी चिकित्सा पद्धति है । मैं यह समझता हूं कि यह घोर अज्ञान का सूचक है– आपकी निगाह से शायद चूक गया हो लेकिन जिस किसी अफसर ने यह ड्राफ्ट तैयार किया है उसको शायद पता नहीं है कि आयुर्वेदिक क्या होता है । वित्त मंत्री जी, इस शब्दावलि को निकालिये, आयुर्वेद पर ड्यूटी खत्म कीजिये और भगवान के वास्ते इसे वैकल्पिक सिस्टम, आल्टरनेटिव सिस्टम आफ मेडिसिन न पुकारिये । यह इस देश की संस्कृति और इतिहास के साथ अज्ञान है । कांस्टीट्यूशन हमको कहता है–

The duty of a citizen is to preserve the culture of his country, the heritage of his country.

[डा मुरली मनोहर जोशी]

आयुर्वेद इस देश का सबसे बड़ा हेरिटज है। सबसे बड़ी विरासत हमने दुनियां को दी है। सारी दुनिया के सिस्टम चरक और सुश्रुत से निकले है। अब आप उसको आल्टर-नेटिव सिस्टम आफ मेडिसिन कहते हैं। ज़रा गौर कीजिये। आप तो एकेडेमिशियन है, शिक्षाविद् हैं, आपकी तरफ से यह हो रहा है। मुझे इस पर बहुत अफसोस है। इन स्वदेशी इकाइयों को बहुत बड़ा खतरा इस नीति से पैदा हो रहा है। आपने 400 रिलीफ्स को वापिस किया है। इन सब चीजों पर आप गौर कीजिये। आप इस सेल्फ इम्पलायमेंट के सेक्टर को तबाह न कीजिये। रूस इसीलिए टूट गया है कि वहां सेल्फ इम्पलायमेंट का सेक्टर नहीं था। पश्चिमी देश इसलिए तबा हो रहे है कि वहां सेल्फ इम्पलायमेंट सेक्टर इतना विकसित नहीं है। सेल्फ इम्पलायमेंट क्षेत्र भारतवर्ष की विश्व को देन है। भारत की अर्थ-व्यवस्था का सबसे बड़ा कुशन है। आपने इस तरह से व्यक्तियों की उद्यमशीलता पर अगर पटाक्षेप किया तो आप इस देश की अर्थ व्यवस्था को खुद तो सम्भाल ही नहीं पाएंगे, आने वाली पीढ़ी को भी आप तबाही के रास्ते पर ले जाएगे। इसलिए मेरा आपसे अनुरोध है कि आप इस क्षेत्र की तरफ ध्यान दें। आप अपने बजट को संशोधित करें और इन लोगों की तरफ जो इस देश की अर्थ-व्यवस्था के आधारस्तम्भ हैं, उनकी तरफ पूरा ध्यान दें।

आज हालत ये है कि आप कहते हैं कि लघु उद्योगों को कम्पीटीटिव बनाना है किस से कम्पीट करेंगे। फूड प्रोडक्ट्स में पेप्सी जैसी कंपनी से कौन कम्पीट कर सकता है? उसको अगर दो सौ करोड़ का घाटा होता है तो कहता है कि मेरे लिए इसके कोई मायने नहीं हैं। उससे कौन कम्पीट कर सकता है? भारत के तमाम लघु उद्योग जो फूड प्रोसेसिंग के काम भी आ सकते हैं, आ रहे हैं, जो तमाम उपभोक्ता सामग्रियों को बना सकते हैं, बना रहे हैं, उनकी क्वालिटी सुधारने के बजाय, उनको अधिक मजबूत करने के बजाय आप उनको नष्ट कर रहे हैं। हवाई चप्पल जिसको आम आदमी, गरीब आदमी पहनता है, उसके ऊपर भी ड्यूटी लगाई गई है। आप चाहते हैं लोग बाटा का जूता पहनें और आम आदमी गरीब आदमी हवाई चप्पल पहनता था किसी तरहसे अपने पांव को कांटों से बचाता था, आप उसकी तरफ ध्यान नहीं दे रहे हैं। उसके ऊपर भी आपकी तलवार चल रही है। नतीजा यह है कि जो एग्रो आधारित कागज की फैक्टरियां हैं, वह भी लड़खड़ा गई है। आपका 1993-94 का इकोनोमिक सर्वे कहता है --

"As a measure of environment protection, pulp made from rice and wheat straws for production of writing and printing paper was exempted from excise duty."

इनवायर्नमेंट प्रोटेक्शन आपका मुख्य उद्देश्य था---

"The excise duty on plywood was reduced frmo 34.5 per cent to 20 per cent. Duty on bulk plastic resins was reduced from 46 per cent to 35 per cent. The duty structure for match industry was rationalised."

फायनेंस मिनस्टर सन् 1993 के बजट भाषण में कहते हैं---

"As a measure of environment protection and in order to save wood, propose to reduce the excise duty on plywood from 34.5 per cent to 20 per cent. I also propose to include pulp made from rice straw and wheat straw in the schme of full excise duty exemption for production of writing and printing paper and uncoated kraft paper containing not less than 75 per cent of pulp made from bagasse, Jute, etc. This will widen the scope for using non-conventional raw materials in the manufacture of paper."

आप 1994-95 में क्या कहते हैं---

"I am enlarging the scope of the exemption currently available to paper mills using non-conventional raw materials. This exemption limits the benefit by clubbing the clearances of paper from more than one factory of a manufacturer. I am now allowing this concession to be availed of by each factory separately."

इसका नतीजा क्या हुआ कि आपने अनकन्वेंशनल रा मेटिरियल जो 50 परसेंट यूज करने वाली बड़ी मिल्ज़ थी, उनके ऊपर 15 परसेंट ड्यूटी है ।

"Use of 75 per cent unconventional raw materail by big mills—Duty 10 per cent use of 75 per cent unconventiolal raw material by small mills—Duty 10 per cent

अब आपसे मैं जानना चाहूंगा कि आप तो रद्दी भी आयात कर रहे हैं। अनकनवेंशनल मैटिरियल कुछ भी हो सकता है । इसलिए बाहर से अनकनवेंशनल सामान मंगाना सस्ता है । आपने हज़ारों हिन्दुस्तान के रद्दी चुगने वाले बच्चों को जो छोटे छोटे लोग कूड़ेदान से रद्दी चुगते थे, उनके पेट पर लात मार दी है । रद्दी का दाम आप देखें, निरंतर गिर रहा है । आप क्या करने जा रहें हैं ? क्या आप रद्दी को आयात करने की इजाजत देंगे ? जब देश में 75 प्रतिशत कागज़ की कमी थी तब आपने इनको यह सुविधाएं दी और इन कम्पनियों ने मिलकर के इस देश के कागज़ के क्षेत्र में आत्म निर्भर बनाया । क्या आप चाहेंगे कि भारत का कागज़ उद्योग आयातित माल के ऊपर चले जबकि देश के अन्दर इतनी बड़ी मात्रा में एग्रो बेंस्ट चीज़ें बची है ? यह इन्वायरमेंट फ्रेंडली हैं आप खुद स्वीकार करते हैं । लकड़ी को प्रेजर्व करना है, यह आप खुद स्वीकार करते हैं । लेकिन मुझे अफसोस है कि आज भारत की सरकार हिन्दुस्तान में रद्दी को आयात करने की इजाजत दे रही है । मैंने अखबार में पढ़ा था-अगर सच है तो मुझे बहुत शर्म होगी कि हिंदुस्तान की सरकार हालैंड से काउडंग भी, गाय का गोबर भी आयात करने की इजाजत देना चाहती है । अनाज यहां से निर्यात करो, बीज यहां से निर्यात करो, फल सब्जी यहां से निर्यात करो और गोबर यहां आयात करो। भगवान के वास्ते ऐसी नीति का आप पालन न करें । अगर यह सच है कि तो मुझे बहुत अफसोस होगा । वित्त मंत्री जी मैं आपसे जानना चाहूंगा और मैं इस बारे में गारंटी चाहूंगा कि हिंदुस्तान में आप विष्ठा को, मल को आयात करने की इजाजत नहीं देंगे । यह एक ऐसा खतरनाक रास्ता आप खोल देंगे कि जिससे इस देश की सारी व्यवस्थाओं पर भारी आघात होगा। हिंदुस्तान के पशुधन का आप विकास करें। मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि उसकी तरफ आपका कोई ध्यान नहीं है। आपका ध्यान सिर्फ कुछ कसाईखाने या बूचरीज को खुलवाने की तरफ है, लेकिन आपका ध्यान हिन्दुस्तान के पशुधन का विकास करने की तरफ नहीं है । हिन्दुस्तान में व्हाइट रिवाल्यूशन लाने की तरफ नहीं है । हिंदुस्तान के इस पशुधन को जो बहुत भारी मात्रा में एनर्जी का स्रोत है, ट्रांसपोर्ट का स्रोत है, सस्ता स्रोत है, परम्परागत स्रोत है, ग्रामीण लोगों के विकास का स्रोत है आपका उसकी तरफ बिल्कुल कोई ध्यान नहीं है और आप जो कुछ करने जा रहे हैं मैं आपसे कहना चाहूंगा कि आप इस नीति को बदलें । इस एग्रो बेस्ट मैटीरियल में से क्या चीज बाहर से आ रही है उसको देखें और इन मिल्स के साथ जो अन्याय आप करने जा रहे हैं जो एग्रो बेस्ड सामग्री से, बुगास से और भारत में मिलने वाली चीजों से कागज बना रहे ह उनका कम स विदर्शा आयात के समकक्ष न रखें यह मेरा आपसे प्रबल अनुरोध होगा । अन्यथा मेरा यह अनुमान है कि आप बजट को जिस दिशा में ले जा रहे है वह दिशा देश के लिए अच्छी नहीं है ।

जो ड्यूटीज ग्रांर टैरिफ्स का सवाल है उसमें हमारे एक प्रश्न के उत्तर में इस्पात राज्य मंत्री जी ने जवाब दिया था कि---

"The performance of the mini steel industry has been affected for various reasons, such as high power

[डा मुरली मनोहर जोशी]

tariff, increase in input cost especially due to rise in international scrap prices."

फिर वे यह कहते हैं कि---

"As per information available, out of 180 commissoned electric are furnace units, 85 units have been lying closed as on date."

फिर वे कहते हैं---

"Besides the reasons stated above, the overall recession in the market as well as in many cases, financial problems have also been reported as reasons for their closure."

चार मार्च को मेरे एक सवाल के जवाब में फिर मुझे बताया जाता है कि---

"The public sector undertakings engaged in the production of copper, zink, lead and aluminium were adversely affected during 1993-94 on account of the fal in the international prices of these metals and lowering of the Customs Duty."

दोनों चीजें आपने कर दी वहां दाम भी घट गया यहां कस्टम ड्यूटी भी घटा दी। इस कारण से आपके माइनिंग क्षेत्र में काम करने वाले, इन तमाम उद्योगों में लगने वाले लोगों के सामने बहुत बड़ी संख्या में बेरोजगारी है और इस्पात मंत्री ने मुझे भी बताया था कि इन स्टील मिल्स के, मिनी स्टील मिल्स के बंद हो जाने से 1993--94 में 18,408 persons have been reportedly affected due to the closure of these units.

यह है बाल्यूम बेरोजगारी का जो आपकी नीतियों से हर क्षेत्र के अंदर जुड़ता जा रहा है। लघु क्षेत्र---और यह मिनी क्षेत्र है---यह थोड़ा या उससे बड़ा क्षेत्र है इसमें भी आपकी नीतियों के परिणामस्वरूप रोजगार उत्पादन नहीं हो रहा है, रोजगार निरंतर गिरता चला जा रहा है। इसलिए मुझे बड़ी भारी चिंता है कि देश की एक सबसे बड़ी समस्या जो रोजगार देने की है उसकी तरफ आपका बजट कोई ध्यान नहीं देता और जो अनआर्गेनाइज्ड सेक्टर है जो भारी पैमाने पर बिखरा पड़ा है मैं नहीं समझता कि आपकी तमाम आर्थिक समक्षीक्षाओं और बजट के प्रावधानों में उसकी दुर्दशा के बारे में उसकी बदकिस्मती के बारे में कोई ख्याल किया गया है। मेरा आपसे अनुरोध होगा कि आप बजट के उन तमाम प्रावधानों को बदलें जो हमारे देश के इस बड़े भारी सेक्शन्स की उपेक्षा कर रहे हैं।

कृषि का क्षेत्र---पिछली बार भी मैंने जो बात कही थी वह फिर से दोहराना चाहता हूं कि आपके हर बजट भाषण में हर आर्थिक समीक्षा में कृषि के बारे में बहुत अच्छे शब्द कहे जाते हैं। कृषि के बिना इस देश का विकास नहीं हो सकता। कृषि के अंदर निवेश किये बगैर इस देश का उद्धार नहीं हो सकता। कृषि हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी है। लेकिन कृषि पर इन्वेस्टमेंट आपका लास्ट प्रायोरिटी है। आप कृषि के क्षेत्र को किस तरह से उपेक्षित कर रहे हैं? इसके बारे में आपके इकनामिक सर्वे के पेज 12 पैरा 60 में लिखा हुआ है कि कितनी प्राब्लम है जिनको आप सुधारना चाहते हैं लेकिन आप सुधार नहीं पाये हैं। आप जरा एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन को देखें क्योंकि अगर ठीक ढंग से इन्वेस्ट किया गया होता तो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन स्थिर न रहा होता। 186 मिलियन टन्स---यह लगभग स्थिर है। इसमें आपके बजट का कोई सहयोग नहीं है। यह भगवान इन्द्र की कृपा है कि पिछले तीन चार सालों से लगातार ठीक मानसून हो रहा है। यह आपका भाग्य है, देश का भाग्य है कि लगातार तीन चार सालों से और मुझे खतरा है कि कहीं इस बार वह फेल कर गया---मैं भगवान से मनाता हूं कि वे फेल न करें...। बावजूद आपके भी वह इन्द्र भगवान समय पर वर्षा करें आपकी

तमाम नीतियों के गलत होने के बाद भी कृषि में वृद्धि होने के बाद भी जहां आप किसान का गला घोंटने के लिए तैयार हैं, वहां भगवान इन्द्र उसको बचाने के लिए तैयार हैं । वह समय पर बारिश करके उसको बचा लेते हैं । आपके यहां केवल 30 प्रतिशत भूमि सिंचित है, 70 फीसदी भूमि असिंचित है और जो भी आपने सिंचन क्षमता का निर्माण किया है उसको भी मैं आपको बताना चाहता हूं कि उसमें 8.3 मिलियन हेक्टेयर्ज की पोटेंशल का गैप है आपके पास 8.3 मिलियन हेक्टेयर्ज सिंचाई वाला पानी मौजूद है डैम्ज में, रिजर्वायर्ज में, लेकिन आप उसका उपयोग नहीं कर पा रहे हैं । आप उसको छोटी और लघु सिंचाई योजनाओं के माध्यम से गांवों में नहीं पहुंचा पा रहे हैं । क्यों बड़ डैम बनाने में बड़ी योजनाओं के अंदर किक-बैक्स भी बड़े होते हैं । लेकिन ये लाख, दो लाख की, चार लाख की योजनाएं होती हैं इसको बनाने में आपके ब्यूरोक्रेट्स की, आपके अधिकारियों की कोई रुचि नहीं है । जिला प्रशासनों में आप देखेंगे आज लघु सिंचाई योजनाओं की तरफ भारी उपेक्षा है । मैं चाहूंगा कि आप इस कृषि की तरफ ध्यान दें । यह 70 फीसदी लोग इस कृषि पर निर्भर करते हैं । कृषि और कृषि उत्पाद के अंदर वृद्धि के बगैर भारत की अर्थ व्यवस्था नहीं सुधर सकती । आपका सबसे बड़ा एक्सपोर्ट पोटेंशल भी अगर इस देश में होगा तो वह कृषि में होगा । इसलिए आपकी इन्वेस्टमेंट प्रायरिटीज बदलनी चाहिएं । जो कुछ आप इन्वेस्टमेंट बड़े भारी सैक्टर्ज में कर रहे हैं, बराय मेहरबानी वहां से निकाल कर उसे यहां लाइये । पब्लिक सक्टर को डिस्इनवेस्ट कीजिए । मैंने आपसे मिल कर भी कहा था कि एक डिस्इनवेस्टमेंट कमीशन की आप स्थापना करें जो पब्लिक सैक्टर को डिस्इन्वेस्ट करे और भगवान के वास्ते डिस्इन्वेस्टमेंट करने के बाद उसे अपनी सरकारी खर्चों में न लगा दें, उसमें आप अपने कर्मचारियों की और अधिकारियों की तनख्वाह बांटने में न लगा दें, उसका उपयोग आप विदेशी कर्जे को चुकाने में करें । मेरी जहां तक स्मरण-शक्ति याद देती है राजा चलैय्या ने भी यही कहा था कि आप इसको डिस्इन्वेस्ट करें और इससे सब से पहले आप कर्जा चुकाएं और डिस्इन्वेस्ट को ट्रांसपेरेंटली केवल इक्विटी ट्रांसफर का मतलब डिस्इन्वेस्ट नहीं है और यह आप ले करके कैपिटल रिसीट्स में दिखा देते हैं । बजट के आंकड़ों से आप कब तक इस तरह से बहलाते रहेंगे, मैं कहना चाहता था :

"तमन्नाओं में कब तलक जिंदगी उलझाई जाएगी,

खिलौने दे के मुफलिसी कब तलक बहलाई जाएगी ।"

श्री इन्द्र कुमार गुजराल (बिहार) "तमन्नाओं में उलझाया गया हूं, खिलौने दे के बहलाया गया हूं ।"

**डा० मुरली मनोहर जोशी** . यह बिल्कुल ठीक है । यह गुजराल साहब ही आपको यह जवाब दे सकते थे । "I am an incorrigible optimist."

जैसा कि आपने कहा था लेकिन वित्त मंत्री जी Optimism is no substitute for hunger. Optimism is no substitute for unemployment. Optimism is no substitute for medicines. Optimism is no substitute for housing.

इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आप इन तमाम नीतियों को बदलें । सरकारी खर्चों पर आपका कोई नियन्त्रण नहीं है । हमने एक सवाल पूछा था कि सरकार के एक्सपेंडीचर में किस तरह से आप खर्चे कर रहे हैं, क्या खर्चे कर रहे हैं । जवाब देने वाले मंत्री जी श्री एम० वी० चन्द्रशेखर मूर्ति विद्यमान हैं, हमारा प्रश्न था : "Whether the Government's attention has been drawn to the news item captioned.

"सरकारी खर्चे में कटौती की योजना मखौल बन कर रह गई" एपीयर्ड इन "जनसत्ता" इसका जवाब है, "यस सर" ध्यान में आपके यह बात भी आ गई । सवाल था :

"Whether it is a fact that the Prime Minister had announced in 1992 that a drastic cut would be made in the Government expenditure. If so, what are the main areas where cuts were proposd"?

जबाब था :

"The Prime Minister had announced several measures to reduce expenditure in his address to the National Development Council in 1991 which inter alia (i) reduction in posts at various levels; (ii) ban on First-class air travel; (iii) surrendering of at least 10 per cent of telephone lines."

फिर हमारा जब सवाल था :

"Whether the Cabinet Secretariat has made any assessment. If so, what are the findings? Whether Government had made any savings during the last three years as compared to 1990 in the expenditure of telephone bills petrol and travel expenditure If so, what are the details thereof, and the reasons if any, for the Government not being able to contain expenditure in Government offices"?

जवाब सुन लीजिए :

"(c), (d) and (e), keeping the Government expenditure under control is a continuous exercise. Instructions are issued from time to time regarding measures to be taken to effect economy in expenditure." The last line is very interesting, "the information in regard to saving on account of these instructions is not maintained."

The Minister states this in the House.

इसी तरह से रिजर्व बैंक को इंस्ट्रक्शंस तो इश्यू कर दी, लेकिन स्कैम हो गया और आप बैठे देखते रहें । इसलिए म आपसे कहना चाहता हूं कि आप इन तमाम चीजों की तरफ ध्यान दें ।

4.00 P.M.

अब आपने जिन दो बड़ी चीजों की वाह-वाही लूटी थी, उनमें से एक तो आपने डिफेंस की बात कही थी और दूसरे साइंस एंड टैक्नोलोजी की बात कही थी । इन दोनों के बारे में कहकर मैं अपना वक्तव्य समाप्त करूंगा । वर्ष 1981-82 में जी.डी.पी. का 2.4 परसेंट रक्षा पर व्यय हुआ था । वर्ष 1993-94 में वह घटकर 1.7 परसेंट रह गया जबकि चीन और पाकिस्तान में यह 6 परसेंट है । रक्षा पर किया जाने वाला व्यय, सुरक्षा के साथ-साथ रोजगार और औद्योगिक विकास को भी बढ़ा सकता है, लेकिन आप उसकी तरफ ध्यान नहीं दे रहे हैं । हमारे काफी इम्पोरटेंट प्रोग्राम्स हैं डिफेंस के जिनकी तरफ आप ध्यान नहीं दे रहे हैं । "अग्नि" मिसाइल का विकास हमारे लिए औद्योगिक दृष्टि से, प्रतिरक्षा की दृष्टि से, देश के सम्मान की दृष्टि से और देश की सेनाओं को सन्नद करने की दृष्टि से बहुत जरूरी है । मैं वित्त मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि बोफोर्स तोप के बाद हिंदुस्तान की सरकार ने अपनी प्रतिरक्षा के अंदर कौन-कौन से उपकरणों को जोड़ा है ? भारत की फौजों को माडर्नाइज करने के लिए, उसे नए-नए अस्त्रों से सन्नद करने के लिए आपने क्या किया है ? क्या आपका यह ख्याल है कि जब कभी इस देश की सीमाओं पर, भगवान न करे कोई हमला हो, तो क्या आप किसी फिल्म एक्टर को वहां ले जायेंगे और वहां गाना गाएगा कि, "हमारे अंगना में तुम्हारा क्या काम है" और दुश्मन की सेनायें वहां से चली जायेंगी ? भगवान के वास्ते देश की प्रतिरक्षा के साथ मजाक मत कीजिए । देश की प्रतिरक्षा के खर्चे की तरफ बराबर ध्यान दीजिए । मैंने उसका विश्लेषण किया है, परंतु मैं उसके विस्तार में नहीं जाना चाहता, लेकिन खर्चों का अधिकांश भाग इनफ्लेशन को बराबर करने में और पेंशन तथा तनख्वाहों में गया है । महोदया'

देश की प्रतिरक्षा के लिए जरूरी है कि देश में प्रतिरक्षा से संबंधित जो रिसर्च एंड डवलपमेंट का कार्य हैं, उसकी तरफ आप पूरा ध्यान दें । महोदय, मैं विज्ञान का विद्यार्थी हू और प्रतिरक्षा की बहुत सी वैज्ञानिक लेबोरेटरीज के बारे में जानता हूं । उनकी तरफ हम जब तक ध्यान नहीं देंगे, उनका विकास नहीं करेंगे तब तक आपको सेक्यूरिटी इंडेजिनस के उपकरण प्राप्त नहीं हो सकेंगे और आप अपनी प्रतिरक्षा को भी दूसरे देशों के साथ जोड़ नहीं सकेंगे । इसलिए मेरा आपसे अनुरोध है कि यह बार-बार जो समझाया जाता है कि आप प्रतिरक्षा व्यय को कम कीजिए, ठीक नहीं है । महोदय मैं फिजूलखर्ची को कम करने के हक में हूं। मैं प्रतिरक्षा को साइंटिफिक और मार्डन बनाने के हक में हूं, लेकिन प्रतिरक्षा के खर्च को बढ़ाकर यह वाह-वाही मत लूटिए कि हमने खर्चा तो बढ़ा दिया, लेकिन उसका एचुचल फिजीकल टार्गेट से कोई ताल्लुक न हो ।

वह देश की सेनाओं को सन्नद करने के काम में न आए, वह देश की सेनाओं की फायर पावर बढ़ाने के काम में न आए। इसलिए टीथ टू टेल रेशियो का ख्याल करते हुए गौर कीजिए कि किनको मजबूत करना है ? आज हम देखते हैं कि 18 हजार में ज्यादा ए.के. 47 रायफल्स तो पाकिस्तान ने हमारे यहां जो मुजाहिदीन भेजे हैं, उनसे हमने पकड़े हैं। तो हमारी सेनाओं के पास कितनी ए.के. 47 रायफल्स हैं ? हमारे देश में ऐसे कितने उपकरण हैं जिनके आधार पर हमारे देश के सैनिक जिस मुस्तैदी के साथ, अपनी देशभक्ति के साथ जान देने के लिए वहां खड़े हैं, जिस विश्वास के साथ खड़े हैं, वह वहां लड़ने के लिए तैयार हों। यहां मैं प्रतिरक्षा के साथ-साथ एटोमिक इनर्जी की भी बात करूंगा और कहूंगा कि आप परमाणु बम के निर्माण के लिए पूरा रास्ता तैयार कीजिए। देश को परमाणु शक्ति से सन्नद कीजिए । देश की सेनाओं को आत्म-विश्वास के साथ जगाइए कि भारत के पास एटम बम होना चाहिए ।

यह आपका सेमी कंडक्टर कांपलैक्स जल गया, इसमें आग लगी, उसके क्या कारण थे ? मैं उस मीमांसा में नहीं जाना चाहता, लेकिन दुनिया के तमाम देश हमारे ऐसे तमाम रिसर्च प्रोजेक्ट्स को सेबोटेज करने में रुचि रखते हैं । इसकी तरफ ध्यान देना होगा । रिसर्च का विकास हमें करना होगा । अगर आज अमरीका हमें सुपर कम्प्यूटर न दे तो हमारे वैज्ञानिक सुपर कम्प्यूटरों का विकास कर सकते हैं, शायद अमरीका से बेहतर उससे ज्यादा जैनरेशन वाले विकास कर सकते हैं, लेकिन आपके यहां सेमी कंडक्टर की प्लानिंग की तरफ ध्यान नहीं दिया जाता । उसकी तरफ भी ध्यान दें ।

आपने एटामिक एनर्जी की तरफ भी कोई खास ध्यान नहीं दिया है । उसके आंकड़े भी वैसे के वैसे ही हैं । वर्ष 1993-94 का रिवाइज्ड एस्टीमेंट था 931.8 करोड़ का और 1994-95 का बजट एस्टीमेंट है 958.82 करोड़ का । यानी वर्ष 1993-94 के बजट एस्टीमेट 965 करोड़ से यह कम है । आपने न्यूक्लीयर पावर कारपोरेशन के बारे में पिछली बार कहा था कि वह 780 करोड़ बाजार से उठाए, लेकिन वह कुछ नहीं कर सका और आपने 260 करोड़ रुपए का उसके लिए बजटीय प्रोवीजन किया । आप ऐसे अव्यावहारिक लक्ष्य क्यों रखते हैं ? इस तरह आप इस एटोमिक एनर्जी प्रोग्राम के साथ खिलवाड़ क्यों करते हैं ? फिर आपने डी. एस. टी. के बजट के लिए बहुत वाहवाही ली। मुझे बड़ी खुशी हुई होती अगर डी. एस. टी. का बजट वाकई बढ़ा होता । मैं विज्ञान का विद्यार्थी हूं, जैसा मैंने कहा और मैं जानता हूं और मैं इस बारे में बहुत गंभीर हूं कि इस देश में बिना विज्ञान और टैक्नोलौजी के विकास के हम बहुत से अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्रों में टैक्नोलोजी से कम्पीट नहीं कर सकते । अगर आप सही मायने में रुचि रखते हैं और सुधार करना चाहते हैं, इस देश में आर्थिक सुधार करना चाहते हैं तो इस देश में रिसर्च के लिए आपको उदार होना चाहिए । मैं आपसे यह कहना चाहता हूं कि फंडामेंटल रिसर्च की हालत इस देश में बहुत खराब है, जबकि जो आज

[डा. मुरली मनोहर जोशी]

की फंडामेंटल रिसर्च है वह कल की टैक्नोलोजी होती है । मैं आज इस पर विस्तार से नहीं बोलना चाहता, लेकिन आप दुनिया में कहीं भी जाकर देख लें, जो 25 साल पहले फंडामैन्टल रिसर्च थी वह आज टैक्नोलोजी बन कर आई है, जो 50 साल पहले फंडामैन्टल रिसर्च थी वह भी आज टैक्नोलोजी बनकर आई है ।

मैं पूछना चाहता हूं आपने यूनिवर्सिटी के लिए यूनिवर्सिटी ग्रांटस कमीशन के लिए, डी.एस.टी., के लिए सी.एस. आई.आर. के लिए, क्या किया है ? ...(**व्यवधान**)... कुछ नहीं है, आप बजट का विश्लेषण कर लें । चूंकि समय समाप्त हो गया वरना मैं विस्तार से बताता । आपने सी. एस. आई.आर. को वर्ष 1993-94 में 320 करोड़ रुपया दिया और वर्ष 1994-95 में 338 करोड़ रुपया । अब यदि 10 परसेंट इन्फलेशन हो गया तो एक्चुअली तो कम हो गया आपका पैसा । इसी तरह से आपने डी.एस.टी. में 189 करोड़ से बढाकर 225 करोड़ कर दिया, लेकिन जो आपने 36 करोड़ बढाया है उसमें से 23 करोड़ तो सिर्फ एक प्रोजेक्ट एडवांस रिसर्च सेंटर के लिए है । लेबोरेटरीज की आज हालत क्या है ? ...(**व्यवधान**) .. मैं वित्त मंत्री जी से बोल रहा हूं । लेबोरेटरीज की क्या हालत है ? आपने डी.एस.टी. की किस-किस शाखा के लिए, किस किस लेब्रोरेटरीज के लिए कितना-कितना प्रावधान बढ़ाया ? एक-एक सैक्टर के लिए आपने क्या ध्यान दिया है ? मैं विस्तारपूर्वक उसका विश्लेषण कर सकता हूं, लेकिन उपाध्यक्ष महोदय की घन्टी मुझे बार-बार दबा रही है ।

महोदय, मैं आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं कि यह वह महत्वपूर्ण मुद्दे हैं जिनकी तरफ सरकार का ध्यान जाना चाहिए । आप केवल मल्टीनेशनल को इस देश में बुलाने के लिए उन्हें सुविधा देने की तरफ जितना ध्यान देते हैं अगर उसका एक चौथाई ध्यान भी आप इस देश में रिसर्च की तरफ, इस देश के गरीब आदमी को ऊपर उठाने की तरफ, इस देश में स्माल स्केल इंडस्ट्रीज को, एग्रीकल्चर को बढ़ावा देने की तरफ दें तो फिर मैं मान सकूंगा कि आप देश की अर्थव्यवस्था के साथ न्याय करना चाहते हैं । वित्त मंत्री जी, मुझे अफसोस है कि पिछले तीन सालों की निरन्तर असफलता के बाद इस वर्ष 1994-95 के बजट के प्रति मैं बहुत ही चिन्ताकुल हूं । देश की गरीबी और मुद्रास्फीति के प्रति मेरे मन के अंदर भारी चिंता उत्पन्न हो रही है और मुझे शक है कि जुलाई पहुचते पहुचते 12 परसेंट से 14 परसेंट तक इस देश में इन्फलेशन की दर होगी और आप उसे संभाल नहीं सकेंगे । भगवान इस देश के लोगों को, आम आदमियों को शक्ति दे, वह बावजूद आपके इस देश को चला सकें और इस देश की अर्थव्यवस्था को सुधार कर रख सकें । धन्यवाद ।

SHRI JAGESH DESAI (Maharashtra): Mr. Vice-Chairman, Sir, I have heard very patiently Dr. Joshi I thought that after giving the emerging picture of the economic scenario, he would give some suggestions on how to improve it. I am sorry that he has not given any suggestions how it can be improved. But I will try to give my own suggestions for the purpose of improving the economy. What has happened? When this Government took charge, what was the economic situation? It is not only once. Whenever non-Congress Government was in power and by the time they left, they had put the economy in total chaos. It happened in 1979 when the Janata Party was ruling. At that time, Dr. Murli Manohar Joshi's party was also in the Government. During the course of 21 months, what was the situation?

There was a negative growth in GDP, there was a negative growth in industrial production; and there was a whopping 21 per cent inflation. Again, when we came to power, in the first year itself, inflation was in

the single digit. The growth of industrial production was 7 to 8 per cent. And that is how the Congress Government, when they came to power, tried to put the economy on the rails. But what happened in 1991? It was the Janata Dal, supported by the BJP, which was in power. When they left, what was the situation?

**श्री अनन्त राम जायसवाल :** (उत्तर प्रदेश) : आप भुल जाते हैं कि 1979-80 में जो जबरदस्त सूखा आया है, सदियों पहले उस तरह का सूखा नहीं आया ।

**उपसभाध्यक्ष (श्री शंकर दयाल सिंह) :** चलए, इसमें बहस की गुंजाइश नहीं है

SHRI JAGESH DESAI: I am talking about 1990-91 when they were in power. I want to show that you never did anything, you never cared for anything. You only wanted to fight and fight and nothing else. That is what I wanted to point out. There were contradictions. You had no policy. But we have a policy...

SHRI DIGVIJAY SINGH (Bihar): That is why we are here.

SHRI JAGESH DESAI: Please listen to me. When we were in power, we steered the situation. In 1991, what was the situation? The foreign exchange reserves were one billion dollars, inflation was 16 per cent, and industrial growth was in stagnation. And as such, when this Government came to power, we started afresh, we had a new industrial policy, and reforms were there. Though the picture was not so rosy and might not have been liked by me, the Finance Minister said in his Budget speech also that the industrial production hda gone up. In 1991-92, it was minus one per cent growth. Last year, it was 1.5 per cent. growth. This year, he expected 4.5 per cent. But, here, I have to give some warning signal to the Finance Minister. What is the composition of this growth? And that is worrying me. As he has rightly pointed out in his speech, the capital goods production is minus 8 per cent. As regards the manufacturing sector, it is an increase of one per cent. I am talking of the current year. But the major increase is on consumer durables by 15 per cent. How will the common man be benefited by this kind of growth? Here, I would like to point out one thing to the Finance Minister. When we give concessions to industry, we should see that the concessions are given for such goods which are for mass consumption. And this situation has to be corrected. In this Budget, you have rightly taken the steps to see that the industrial development and growth goes up to 6 per cent, as against 8 per cent in the early '80s. For that purpose, you have given many concessions to the industry. But last year, when you had given the concessions, they were not passed on to the consumers. Again this year also, you have said that the industrial growth is not there to our expectation. Then again we shall face a situation which we were facing in 1990-91. As such, from now onwards, we have to see that whatever concessions we give to the industries, they are pased on to the consumers. As regards the industrial growth rate, the concessions we give should result in higher production. And the growth of money supply on the 31st December, was 15 per cent. If the growth in money supply is not matching with production, the prices are bound to go up. As such, we have to see the industrial production goes up.

And Doctorsaheb just now said about the Defence sector. So, first of all, I would like to inform Doctorsaheb one thing. As regards Defence, every Indian is concerned that we have to spend on defence production so that we can face any eventuality. This time, there is an increase of 25 per cent as regards the capital outlay for Defence is concerned. In 1993-94, it was Rs. 5500

[Shri Jagesh Desai].

crores and this year it is Rs. 6831 crores, that is, an increase of 25 per cent in the allocation for capital outlay. I am not talking of salaries and administrative expenses. I compliment the Finance Minister for allocating a good amount for Defence Capital outlay.

As regards the public sector, every time it is denigrated and the charge has been that the Government is not helping the public sector. The Government has definitely helped the public sector even in the curent year. I may give some figures here. As regards the budgetary support, last year, it was Rs. 23,241 crores and this year, it is Rs. 27,278 crores— an increase of 17 5 per cent. As regards the Budget allocation...

DR. MURLI MANOHAR JOSHI: You also explain as to what is the internal and external budgetary component.

SHRI JAGESH DESAI: As regards investment in the public sector, at the end of the 7th Five-Year Plan, it was Rs 99 000 crores. The increase in the 7th Five-Year Plan was to the tune of Rs. 57,000 crores. At the end of the 6th Five-Year Plan it was Rs. 46 000 crores and then it became Rs. 99,329 crores. In these three years of the 8th Five Year Plan, that is, for 31-3-91, 31-3.92 and 31.3.93, the increase in investment of the Government is to the tune of Rs 47.000 crores. In the whole 7th Five-Year Plan, it was Rs. 57 000 crores and in the first three years of the 8th Plan, it is Rs 47,000 crores. I would like to make it clear that the policy of the Government is to see that the public sector is given as much as possible according to the resources available and I am happy that the Government is giving large sums of money to the public sector As regards efficiency and the profits of the public sector, I am happy that this year, the profits of the public sector after tax has been Rs. 3,396. Earlier, it was Rs. 2,300 crores. In 1983-84, it was only Rs 240 crores. And the percentage of the profit as regards the investment or the paid-up capital, is 6 to 7. It is 6 to 7 per cent. We are always told that the profit of the public sector is only 2 or 3 per cent, which is not correct. Though there is scope for improvement in the working of the public sector, but to denounce the public sector by saying that it is a drain on our economy, is not correct I would like to suggest that when there is disinvestment of shares in the public sector, after deducting the capital component, 50 per cent of the balance should be used as the Budget resource and the balance 50 per cent should be given to those public sector undertakings which can be revived by modernisation. In this connection, I would like to remind the hon. Finance Minister about the commitment made by the Party at the Surajkund A.I.C.C. Session. The Congress Party is now committed to it, that when the shares are disinvested, market value would be taken and the resources generated from the disinvestment—a major part of it—would be given to the public sector undertakings for expansion and for setting up new public sector undertakings. But I would like to suggest that no new public sector undertakings should be set up Whatever funds are available should be utilised for the purpose of modernisation and technological upgradation of the existing public sector undertakings so that they could produce more goods. As a consequence of this, the cost of production would come down and they would also be able to make more profits.

I would like to make a suggestion here. I have visited a number of public sector undertakings. They have vast chunks of land Thes lands are mostly in the urban areas in the metropolitan cities. They shou

be allowed to sell the excess land and the Urban Land Ceiling Act should not be made applicable. If that is done, they would be able to get resources and, with those resources, they would be able to employ more persons.

Unfortunately, in the case of the public sector, from the study and from the discussions with the different C.M.Ds., I find that there is over-employment. As such, they are not able to make profits to the extent they should. How do we get over this problem? Our Prime Minister had made it very clear at Davos. I congratulate our hon. Prime Minister. He was very very frank and bold. He said: 'I have no right to throw away any person from his job; I will never do that. Those who were sitting nearly 5,000 kms. away did not understand that. This is the policy of the Government. I think the hon. Finance Minister also said the same thing. Recently, when a Japanese delegation met the Prime Minister, he firmly told them: 'No exit policy'. Then, how do we solve this problem? This is the dilemma. As I said earlier, the only solution is that there should be no new public sector undertakings; you should expand the existing public sector undertakings, give funds for them. In this case, there would only be capital expenditure and there would be no additional expenditure on labour. As a result of this, the prices would come down. This is the only solution to make the public sector workable, to see that those who are employed are retained and new jobs are created. Otherwise, the public sector would go to dogs. Over-employment is a curse. We are responsible for it. We, politicians, are also responsible for it. We also ask them to employ such and such persons. As such there is over-employment. This problem can be solved only by the method which I have suggested I am sure the hon. Finance Minister would definitely look into it.

As far as inflation is concerned, everybody is worried. The rate of inflation which was 5.5 per cent some four-five months back has gone up now to more than 8 per cent. It has again gone up this week. It has gone up by 0.15 per cent. It is now almost 9 per cent. Therefore, there should be some kind of a check. But I do not know how you are going to do it. If money supply is more and production is not there, the prices are bound to go up. Administered prices have to be increased. If farmers are given better prices, the Government cannot bear that burden. It has to be passed on. We have to find a way out as to how we can do it. The only solution, according to me, is more production and the industrial stagnation which is there has to be removed.

In the case of direct taxes, I see that your proposals have a human face. In the case of senior citizens like me, who are above 65, the rebate was 20 per cent; you have increased it to 40 per cent. The income limit was Rs. 75,000; you have increased it to Rs. 1 lakh. This is how you have tried to help the senior citizens. Perhaps, after retirement, it would help them. Similarly, in the case of students; you have not forgotton them. Without education, there cannot be any progress.

So far as poor students are covered, their parents take loan. You have given a tax concessions by way of deduction of Rs. 25,000 on interest and reayment of instalment every year and up to Rs. 2 lakh. Sir, I thank you very much for this because I know it myself. I come from a very very poor middle class family. I could not go to college for one year. The people of the town colected money and sent me to the college. So, you have given poor students, who cannot go to college, this kind of avenue, so that they can go to colleges and have better education.

For housing also you have given the help. The deduction was up to Rs. 5,000. Now you have raised it to Rs. 10,000. This will definitely give some kind of encouragement to the middle class people to take loan and construct small houses.

You have also not forgotten the ordinary middle class tax payer. You have increased the tax limit from Rs. 30,000 to Rs. 35,000. I think, this is a reasonable limit because going beyond that will harm the interest of the States. We have to take into consideration the interest of the States also. Eighty five per cent of the income-tax collection goes to the States and the States are also not to be starved of the funds.

Here I want to make one sugestion about service tax. Service tax will be administered by the Central Excise Department, whereas the correct agency for the purpose of administering service tax is the Income-tax Department. Service tax is on the telephone bills. So far as the bills are concerned, the bills of businessmen are debited to their accounts. As the tax rate is 40 per cent, it will come to 3 per cent, whereas for those who are not business people, it will come to 5 per cent. Similarly, it is the business man who gets insured with the General Insurance Company. They can afford to pay 5 percent, but this tax should be administered by the Income-tax Department. Mr. Finance Mnister, I want to suggest that whatever collections are made under service tax should be admitered by the Income-tax Department and they should be passed on to the State Governments to the extent of 85 per cent. You have put it under the Cetral Excise Department so that you have not to pass on the share to the States. I know that you want the revenue for your Central Exchequer but really this kind of tax should have been levied by the State Governments. Since you have taken the powers, I think, 85 per cent of the share should be passed on to the State Governments.

About small savings also every year I have been pleading with you. I thought you would do something. this time. Though you have done something, you do not seem to do anything more than that in haste. My plea is, why not give hundred per cent colection of small savings to the State Governments? That can be done. You are charging 14.5 per cent interest on loan advanced. Why don't you give them 100 per cent so that they will have more resources?

Regarding gift tax, I am not happy. I cannot reconcile myself because this has been my personal view, not from now, but from the very beginning. Gift tax, at the time of dependant relative's marriage, up to Rs. 1 lakh you have exempted. Who will get the benefit? Is it the common man? Why are you shedding your income? What was the necessity of raising it from Rs. 30,000 to Rs 1 lakh? I think you should review this. That is my personal view because I feel that this kind of tax concessions should not have been given because it will only benefit the upper middle class and rich people. We can't give Rs 1 lakh as gift at the time of marriage of our relatives, and I don't know and I am myself not clear whether at the time of the marriage of the dependant relative, the gift to anybody up to Rs 1 lakh will be exexempted or the person who gets married will be exempted. I think that point also needs to be cleared.

As far as small-scale industries are concerned, from the reports that we read in the press we cannot analyze the clamis they make. Wht I made out was that, as far as textiles are concerned, after this new system of excise duty, they will have to pay Rs 1,100 croes more as excise duty, and out of these Rs. 1,100 croes, Rs 900 crores have to be paid by the power loom industry. I don't think you have intended it that way.

THE MINISTER OF FINANCE (SHRI MANMOHAN SINGH): We have not included any tax on power looms.

SHRI JAGESH DESAI: That is why it should be clarified, because that was not your intention. Your intention was to rationalize and you have brought a rationalized system. I am happy about that because, in 1986 when Rajivji was the Prime Minister and Finance Minister, a Committee on Indirect Taxes was appointed, and I was a member of that Committee. We had suggested that and you have implemented it. So I compliment you.

About my suggestion regarding prices, I am happy that we have the highest procurement of foodgrains. It is about 23 million tonnes at present. This will definitely give us the hope that whenever required, they will be available to the people, the vulnerable sections. But, unfortunately, the off-take is going down. The off-take which, in 1992-93 was 11.7 million tonnes, went down to 9.5 milion tonnes, and this is where we have to see that foodgrains reach the vulnerable sections. Otherwise the whole public distribution system will be put to difficulties.

So far as our foreign debts are concerned, Dr. Murli Manohar Joshi was woried about that. But I would like to put the record straight. As regards foreign debts, what we borrowed in the latter half of 1980 was three billion dollars on average per year. In 1990-91 it was eight billion dollars. In 1991-92 and 1992-93 it was brought down, when this Government came to power, to three billion dollars. And this year, in the first six months, it is only 0.3 billion dollars. So the Finance Minister is very much worried about it. He has taken steps and he has seen that this kind of borrowing from foreign countries should be as little as possible, and he has acted accordingly.

So, you cannot charge him that he is creating debts for the country. Not only that, the instalment of $1.4 million, which is to be paid by 31st March, 1995, he has stated in the Budget speech that it will be given at the beginning of the year. I compliment the Finance Minister.

Sir, let us be very firm on this issue. I am sure we will never succumb to the pressures of any country. Now, see China. When Mr Christopher, the US Secretary of State, went to China, the Chinese Foreign Minister told him bluntly that as far as human rights and trade policy and economic policy were concerned, they were different isues. They were not going to succumb to that kind of pressure. When Mr. Christopher was in China, several persons were arrested. They said that was their internal affair. They liked no one's interference. Similarly, our Prime Minister made it very clear that as far as reforms policy is concerned, we shall have to see the results. We have to watch we do not have to rush. But at the same time reforms policy is irreversible. But we have to see the fruits of the reforms policy coming. Of course, it may take time. We should watch and we should carefully go into it. But if liberalisation means that the private sector is to be given free licence, that is not liberalisation. If private air taxi operators are allowed to serve liquor, that is not competition. That is an unfair competition. If this kind of competition is allowed, then the public sector will have a natural death. I don't think anybody in this country wants the public sector a natural death. Everybody wants that the public sector should continue to occupy the commanding heights of the economy. The public sector has served this nation for so many years by building infrastructure industries.

Dr. Sahib, you have talked of profits. In infrastructure industries you cannot expect that much profits as in private sector industries. If you

[Shri Jagesh Desai].

want that power generation or communication or any other such industries should have 10 or 15 per cent return in our country, I do not think that is the correct concept of public sector policy. What we want is that we should channelise our resources. We should make it efficient. The prices should not reflect your inefficiency. According to my yardstick 7 per cent to 8 per cent net profit after tax is quite reasonable. If you take the foreign industries apart, find out where they are not earning a good profit, why they are not earning. If Rs. 2,000 crores is to be spent on social services by the public sector and if you take into expenses, naturally their profit is going to be less. This time the public sector is spending Rs. 891 crores as against Rs. 393 crores on research and development. It means about Rs. 500 crores or more it has to spend. Does the private industry do like that? what is their expenditure on R & D? These are the things to be taken into account. Their results will be felt in years to come. If this is considered as expenses, then naturally the profit will go down. All these adjustments have to be done before the real profit of the public sector is arrived at. So far as the public sector is concerned, their sales turnover has gone up by 9 per cent in the current year. So, things have improved. I have no doubt about it. But it shoud be properly monitored by the nodal Ministry. But they should not interfere in their functioning. You should give the public sector undertakings autonomy. But there should not be any interference. When ever an MOU is entered into by the public sector undertakings you should see that they work according to the MOU If they are not doing, then, definitely you should take action against the Chairman of the concerned public sector undertaking. He should be removed. The working of the public sector has to be improved. If you are not able to do it, then, I think, whatever resources we have invested in the public sector, we will not get proper returns which are expected to them.

My last point is regarding the wealth tax. I am again very unhappy about it. Last time also I spoke about it. You said that in the case of non-productive assets only wealth tax is applicable. That also if wealth exceed Rs. 15 lakhs. Why are you not planning to get resources from the wealth tax? Why is this kind of concession be given? You can give more exemption of weath tax for the productive assets. But you are giving total exemption of wealth tax on the productive assets. I think that this doesn't appeal to me. I hope that when the Finance Minister bring it here next time, he would look into it and see that it is done.

So far as excise duty is concerned, whatever rates you have prescribed, you can remove it. Here small-scale industries have been hit hard. I always plead for small-scale industries. Yesterday, there was a discussion on the T.V. about the steel industry. So, please give us the real picture of the excise duty on the steel. You should provide some relief to the small-scale industries who are engaged in the manufacture of steel so that they can feel that the Budget is not harsh towards them.

Mr. Vice-Chairman, this Budget is meant for the rural people. We want to change the face of the rural sector totally. Compared to last year, forty per cent more allocation has been given to the rural sector this year. Similarly for agricultural sector also, though it may not look like what we wanted. The rural economy has to be improved so that there is no exodous from the rural areas to the urban areas. For example, Bombay. This exodous can be stopped. I am sure that the Minister would ponder over the suggestions which I have offered to him and

wherever possible and if there are resources, he can implement them. Thank you.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI SHANKAR DAYAL SINGH): No name from the Janata Dal party. Now Shri Ashok Mitra.

SHRI ASHOK MITRA (West Bengal): Mr. Vice-Chairman, I rise to speak on the General Budget for the year 1994-95 first, with some diffidence and second, with a feeling of uncertainty. The diffidence is on account of the fact that a colleague of the Finance Minister has reportedly gone on record that only he himself and his Secretary understand the GATT Treaty and nobody else in the country does. If taking the cue from his colleague, the Finance Minister would claim that only he and his Finance Secretary are competent enough to understand the Budget proposals, then, we do not know where we stand. My feeling of uncertainty is for a different reason. I hope the Finance Minister would not claim that he is not accountable for the Budget proposals which he has submitted. I ask this question very pointedly because of certain precedents that seem to have been established in the precincts of this Parliament. Having got rid of these two uncertainties I had in mind, I would like to mke a few friendly suggestions and offer a few friendly citisisms to the Finance Minister. And I would have said what I am saying now even if I happened—God forbid—in be sitting in those benches. What I am saying would be from the bottom of my heart and I would deny that. I am trying in the present intance, to grind any political axe.

The first thing I have to confess to is that reading a second or a third time through the Budget speech, I could see that the Finance Minister, unfortunately, has lost his bearings. I could not discover any structure. Certain individual bits and pieces have been, in a sense, put together. But there is no coherence in what he is trying to say. There is vision in fact, about where we are going, where the country is going, what the problems have been in the current year and why the problems have arisen and what he is going to do to try to cure those problems. To give a simple example, out of the most important elements of the Budget the Government's Income-Expenditure Account, has gone completely haywire. The income or revenue Estimates are Rs. 8,000 crores down and the Expenditure Estimates are Rs. 14,000 crores up. Obviously, the calculations have not worked out according to projections: Between the planning and the execution of the Income and Expenditure Accounts, a big shadow has fallen. Even before the Budget was presented, the Finance Minister did confess that he was having difficulties. There are certain political realities he and his Government have to face. This is bound to happen. You are the Government; you have seized power; and you will use this power to ensure that you stay in power. There is nothing shameful in this. But what I find a little bothersome is the response when pin-pointed questions are asked of the Government. For example, why is the expenditure so much up? My own hunch is that since you were fighting elections in six States, you liked to transfer money to each of these six States. One asks a question of the Minister. And what one gets is an elliptical answer.

I would make a little digression and make an appeal to the Government and the House. After all, it is not a cat-and-mouse game the Government is playing with the Members of Parliament. Members represent the people and they want to know. There should be some transparency between the questions, that Members of Parliament pose and the responses offered by the Government. This is something which is lacking. I am

sure the Finance Minister realises that. Sometimes, you feel that this is politically inconvenient and therefore, you try to stone-wall. But, I would say, in the long run, it becomes counter-active, because once you do not give a truthful answer, you try to shy away from the true answer, then, you really allow the opportunity to the particular Member to build his own hypothesis which does not do any good to the country. I wish I knew how much of extra money has gone to the six States by way of additional expenditure.

The other part of the story is that we know if there is no growth in the system, no industrial growth, there will be repercussions of this stagnation. Obviously, your revenues would fall. I say that one could even sympathize with the Finance Minister. He is a slave of a particular theory of economic growth which has been imposed upon him by outsiders. And the outsiders got this opportunity because the economic policy of this country was conducted in a particularly slip-shod manner between 1984 and 1989.

We are suffering from that legacy. This is the only issue on which I have to differ from my friend, Mr. Jagesh Desai. Otherwise, I could have agreed with a very large part of what he has stated. But anyway, there is no use carying over split milk. Having accepted the preamble of a theorem set from outside, we try to put that into action as the Finance Minister tried to. But other problems arise, the problems of real politik, This problem of real politik is hurting him and it will continue to hurt him even this year because the Government will have to face elections not just in six but, may be in eight or ten States and the same kind of problems that you faced, you would continue to face. Which is why I think that you have fallen back on an optimism, which has no basis, If you initially said that you would keep your fiscal deficit confined to 4.7 per cent of G.D.P. and you end up with a figure of 7.3 per cent of gross domestic product, given the trend of things, perhaps, we are in a position to apply the Rule of three. If 4.7 per cent becomes 7.3 per cent, then 6 per cent deficit which the Finance Minister himself has promised for this year, would become 9.1 per cent. I can then work out what the order of fiscal deficit would be, maybe, 75,000 crores of rupees or, maybe, 80,000 crores of rupees. I do not know. But I would with a bit of more candidness in the way the Budget figures are presented. But the problem is his estimates have gone away on income and expenditure, he must be under some additional pressures from the ladies and gentlemen from the Fund and the Bank, which is why we find that despite the difficulties he has faced in the current year, he has been persuaded to reduce further the level of import duties and to have an across-the.cut reduction in direct taxes. This is the risk that he has taken and this is on the basis of an assumption he is making that if he lowers the duties, then not only the supply side of production will begin to pulsate a bit more but things will happen even on the demand side. I do not think that will happen. The demand-side will not at all be affected. Such things as the lowering of the interest rate, I don't think, would provide any impulse to the demand for goods and services. All that would happen is that perhaps with a certain margin, some entrepreneurs, who, at the moment, are staying away would feel like investing. But how much? It is the total picture that will affect the expectations of the entrepreneurs. Wha is happening in the overall to the total system? Take, for example, agriculture, which is really the fulcrum of the entire system, producing roughly two-fifths of the national income, capital formation there is going down, down and down. It is certainly three to four per cent down over the last three or four years. The capital formation in agriculture basically was the contribution of the public sector. It is the Government which built the Bhakra Nangal Dam, it is a Government which

built the major and minor irrigation systems all over the country and it is a Government which did all the reclamations over the last forty odd years since independence. Now, suddenly, you find that the public investment in agriculture is petering out and it is petering out because of a conscious Government decision which is a consequence of the set of policies you had agreed to with the foreigners two and-a-half years ago. You cannot revise it. I know you have inserted in the Budget certain gestures of additional support to the NABARD or to the co-operative institutions, but they would not really change the overall qualitative nature of the situation we are facing. So, leave out agriculture. In any case, it is fortunate that we have had a succession of half-a-dozen good harvests. What is the Finance Minister banking on? He is banking on the hope that despite very little extra investment the rain-God will continue to favour us? If he doesn't what will happen to prices? In the latest estimate I have seen is of shifting the wholesale price index, the provisional index has risen by 8.8 per cent over the year. This is the provisional index and I checked up the figures for the last few years. I find that between the provisional index and the final index, there is usually an upward shift of; something like, 20 per cent. So, when we nominally suggest is an 8.8 per cent increase, there is actually an increase of 11 per cent which has already come about. If the trends in income and expenditure remain what they are and continue for the next year, I see little reason for not expecting a rise of the order of 15 or 16 per cent fo the whole year. One should still hope that things will be better. But the picture of reality has to be recognised. In such a situation what does the Government do and what ought the Government to have done? What it has done is a sort of surrender. All right, I cannot do anything in pushing up investment because I am already being dressed down. You see the profligacy in my expenditure. Profligacy is the wrong type of expenditure, revenue expenditure; and there is nothing worth mentioning in the capital account on developmetal expenditure. All that has happened is that some of the cuts introduced over the last two years in, e.g., the public works programmes for generating employment have been restored but if one takes the overall Plan expenditure and the price index, there is actually no increase—zero increase I would say—in developmental expenditure. So, we cannot hope for a momentum of growth from the Gnvernment side. The Government has decided to sit it out and hope for things happening elsewhere. What do you mean by 'elsewhere'? Oh, autonomous factors take over,—what are the autonomous factors? The autonomous factors are the factors that might be set in motion as a result of the import duty being cut, as a result of the excise duty being rationalised, as a result of the direct taxes being lowered—the situation could be different. About direct taxes, I do not believe that the lowering of direct taxes would have much effect on demand; may be, demand will grow for the wrong type of goods. Yes, I belong to the middle class. I find at the end of the year I have got Rs. 1,000 or Rs. 2000 extra in my pocket. And given the type of propaganda—if I can use the expression being generated in favour of luxury consumption —I would not use these Rs. 2,000/- to add to the nation's capital formation. Rather we use this money to buy, may be, a washing machine or, may be, a double-door refrigerator.

This is one of the dilemmas the hon. Minister has to solve for himself.. He is targeting for the up-and-coming the middle class which may constitute, 10 per cent of the nation's population; may be, 15 per cent of the population; I have no idea But you are really inviting them to perform two functions simultaneously. You are asking them to buy, but,

[ Shri Ashok Mitra ]

and buy colour television sets on which duties have been reduced, buy washing machines on which duties havs been reduced, by refrigerators, fineries, apparels etc., etc. You are so, in a sense, inviting the same middle class to invest in growth by helping in the process of capital formation. You have to decide in your mind—this is the dichotomy in your economic policy—you cannot ask the people simultaneouly to sustain savings and sustain consumption. The model you have adopted, I am afraid, is flawed. At the same time, some type of a problem has arisen with respect to what you want to do about, for example, the share market vis-a-vis investment in productive activities. You may be again listening to the foregn advice and embarkng on a programme for modernisation and expansion of the stock exchanges. There have been some hiccups. But you have assured us that the hiccups are over and from now on there will be strict regulation of the stock exchanges. We have to take our Finance Minister on trust; otherwise, whom else are you going to trust? Even so, the basic problem arises. You are badly in need of additional capital investment. But you have created an environment where whatever little savings are there you are saying rush, rush, go to the stock markets the capital formation activities, productive activities are being affected. What do you do about it? This is in fact a corollary of the first dilemma. Here again you are saying. there is a certain flow of money income. Let this flow. It should grow for productive investment. But since you have generated so much interest and excitement for the stock exchange, the interests of the would-be investors are getting divided. Therefore, you are just biding time. In the Government sector there is no marked improvement or upward shift in investment and in the private sector it Is a repetition of the same story. What do you do? You necessarily fall back on foreign investment. If our Government cannot expand investment it is because the Goverment is under a strict regime enforced from outside. If the private sector is being led or misled by wrong type of signals then, may be our banors would be the foreign investors. Here again you will find the repetition of the same dilemma. I have asked a question and tried to get answers. I sought answers from the Government and they are the usual stonewalling answers. Routine questions set for the Finance Minister are routinely rebuffed; it needs no repetition. I had asked a simple question. Yes, you said that foreign investments were coming in. The other day the Prime Minister quoted some figures and said that they were evenly distributed among different sectors of the economy. I asked a question of the Finance Minister. What have been the actuals of the total investment that has come in between 1991 and now? We know the approvals. Every fortnight we find a triple banner headline about what the approvals have been. We also find the break-down of the approvals. Some capital goods sectors are also mentioned there. When you ask a question of the Minister: "All right. What have been the actuals ?What is the break-down of the actuals?", I get an stounding answer. "Yes, there are estimates available of the approvals, th break-down of the approvals." All we know is that we can surmise that perhaps during 1993-94 we have got between 1.5 billion dollars and 2 billion dollars of investment from the foreign institutional investors in the stock exchanges but the actual foreign investment for productive purposes would be in the region of 400 to 500 billion dollars. This is where I will do my other arithmetic. What is happening to our external balances Now, the Budget has gloated over the figure of 13 billion dollars of foreign exchange reserves. You see it is just spilling all over asagainst one billion dollar in June, 1991. I wish somebody

would do a research on the story why our balances dip to one billion dollars in the middle of 1991. What had happened between April and November 1989 which had an impact on the figures of June? But let us forget that story. So, from one billion dollars it has come to 13 billion dollars today of which, may be, the contribution of the FIIs and the NRIs would come to 5 to 6 billion dollars. The rest, I wish, I could claim that we have earned. But we have not earned. This is the contribution by foreigners to our state of being. So we are really gloating over borrowed glory. Others have lent us this money and we are bragging about it. I am not worried about that. After all there must be something which the poor foreign investors must gloat over. So, we can grant him this fact that one billion dollars has become 13 billion dollars But what about the flip-side? I had asked of this Ministry a question. What will be the debt service repayment during 1994-95, 1995-96 and 1996-97? I think they have a brilliant officialese of an answer. They will say. "When 1994-95 is not yet over, how can we say what will happen? It will depend upon our current economic position and it will depend upon how much we borrow, etc. etc." So, we cannot give you the answer. But you are running a Government. You must have some figures at the back of your mind. What will be the debt repayment obligations in 1994-95, 1995-96 and 1996-97? I would say, "All right; as I belong to the Opposition, you don't have to give the figures to me." But I hope that you have kept these figures in mind. I have seen some estimates prepared by a Committee which was presided over by the Governor of the Reserve Bank of India. On the basis of what I got from the table that has been furnished in that report, my own assumption is that over these three years the total repayments that we would be called upon to make, will be around 30 billion dollars or as high as be billion dollars if meanwhile the things fluctuate a little bit. Where will the Finance Minister get this money? Now, I don't honestly believe that he can get this much money from exports. Already, there is some suspicion that the kind of figures about the export growth, that are being bandied about, there must be some blemish in them. Some people say that some of the Hawala money that had gone out of the country is being brought back through over-invoicing of exports. I don't know about it. I think the Finance Minister will be the best judge to enquire what proportion of the total nominal increase in exports is on account of such factors. I don't think exports, by themselves, can give this money. I have made my own calculations. I think we need a minimum of even to eight billion dollars of direct foreign investment over the next three years, if this crisis of debt service obligations is to be met with confidence. Would we get this much of money? In order to get this money what additional persuasive measures do you have to adopt? How much of national dignity would that kind of a concession cost us? These are the questions which have to be raised over again. Meanwhile, I would merely suggest to the Finance Minister that he should have at least a second book of accounting You gave away Rs. 4100 crores of tax money, despite your experience of this year and then you claim that this will be recovered because you have adopted this method. You said that this kind of rationalisation will allow you to do it and you used sophisticated expressions like Laffer principle or whatever it is. But we have had experiences even in this country. I remember, when Mr. Y. B. Chavan was the Finance Minister in 1973-74 or thereabouts, there had been a reduction in the direct tax rates in the hope that this would generate extra income for the Government. This had been done and you can call it by whatever name you like. But I do not think, emperically, you can really prove that this is going to happen. You have to build castles

[ Shri Ashok Mitra ]

in the air. You have built castles in the air. But suppose nobody shoots down these castles. In that case, what is your second line of defence? How wil you manage your economy? Ultimately, they will say that there is division of labour and it is for the poor Minister of Finance to ensure that things are kept on an even keel. What would you do? would you cut down further your developmental expenditure? What will be the impact of that on the total system? I would merely appeal to the Minister. We know what the World Bank has in its mind. They have a model of growth. They do not have to worry about the problems of income distribution. They do not believe that income distribution is an element which would affect the process of income distribution. Once you have growth, the problems of income distribution would automatically be taken care of. What is there on their mind is perhaps the model of Brazil, the entrepots of Sau Paulo, Rio de Jeneiro and Brasilia.

The rest of the country is in a huge pool, stagnating. If not stagnation, perhaps over this vast stretch of area, what is going on is a process of what is known as development of the under developed. We are sinking and sinking and sinking. Is that what you have in mind? Let me be a little more personal. I cannot forget the fact that I represent West Bengal. You have adopted an economic policy and one important element of this economic policy is that the public sector must be shut down—the Government must be the major saboteur of the Government sector. Now, this in effect is what you are doing. What you are doing has a two pronged effect: (i) the better public sector units, you are selling off in the manner of—let us say—an impoverished feudal family which sells all its jewels, pots and pans. You are doing exactly that. Disinvestment— it aught to be a matter of shame. When I see that the Government expects to disinvest Rs. 2500 or Rs. 3500 crores worth of public sector assets... (*interruptions*)...

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI SHANKAR DAYAL SINGH): Your time is over.

SHRI ASHOK MITRA: Can I take another five minutes? After that you can chop off my head. The second strategy that you have adopted is to deny them working capital funds so that they can slowly bleed to death, starve to death. What are the other implications, Mr. Finance Minister? We read in the newspapers that you represent an eastern State. The Chief Minister of eastern State tried to draw the attention of the powers that be in New Delhi to what the new economic policy was doing to the state of employment in Assam. I know what it is doing to the state of employment in West Bengal—Fifty-five thousand people in the wagon building industry, another 30 to 40 thousand in the fertilizer industry. I could up-date the list. It is not their fault that these public sector units were set up in that area way back in the 1950's and 60's. Various Governments were in power. But it was the Government of the Indian National Congress which set up these units. And now you tell the people that you have no responsibility. You are reluctant at large. I tried to impress on the Railway Minister, "Yes, we have come here to ask gentlemanly questions about what you can do." But it is pointless to raise gentlemanly questions because soon the entire matter will go out of their hands. Thousands and thousands of unemployed young people have no livelihood. You are cutting off their livelihood. That is that your policy implies. What will they do? We may stay gentlemanly because we are under the rules and regulations of this House. But, outside, what will they do? That will be the reality. We talk about the People's War Group in Hyderabad. We talk